A Daily News Magazine
इंदौर
मंगलवार, 26 नवंबर, 2024

सुबह सवेरे

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 10 अंक 59, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2 (डाक पंजीयन संख्या: MP/IDC/1529/2016-2018)

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

मणिपुर: निर्णायक कदम उठाने से भाजपा को क्या रोक रहा है?

मोनीदीपा बनर्जी

वह वक्त जब ऐसा लगा कि केंद्र मणिपुर में निर्णायक कदम उठाने वाला है - आखिरकार - तब था जब गृह मंत्री अमित शाह ने 17 नवंबर को महाराष्ट्र में अपना चुनाव अभियान बीच में ही रोक दिया और नई दिल्ली वापस चले गए। माना जाता है कि वे पूर्वोत्तर राज्य में पिछले 19 महीनों से लगातार जल रही और सुलग रही इस आग को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस पर हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए मुख्यालय पहुंचे थे। इसके अलावा, केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार, जो मणिपुर में डबल इंजन वाली सरकार का दावा करती है, ने राज्य या देश के बाकी हिस्सों को यह भरोसा दिलाने के लिए कुछ नहीं किया है कि मणिपुर मायने रखता है, लेकिन शाह के दिल्ली लौटने के बाद से केंद्र ने क्या किया है? राज्य में और अधिक अर्धसैनिक बलों को भेजने और छह पुलिस थानों के क्षेत्रों में विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) लगाने के अलावा-कुछ नहीं।

गलत, अमित शाह अपनी उंगली हिलाकर संदेह करने वालों से कह सकते हैं कि यह केवल उनके हालिया हस्तक्षेपों की वजह से है कि जिरीबाम जिले के बाद से राज्य में कोई नई मौत नहीं हुई है, जो 7 नवंबर को आग की लपटों में घिर गया था और 10 दिनों में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन 500 से अधिक दिनों के हिंसक उपद्रव में से केवल पांच दिनों तक कोई हत्या नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं है।

मणिपुर में 3 मई 2023 से मैतेई-कुकी हिंसा में कम से कम 250 लोग मारे गए हैं, जब मैतेई लोगों ने कुकी की तरह अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांगा था। जिरीबाम जिले में हिंसा के बाद एक बार फिर तनाव बढ़ने के 19 महीने बाद, राष्ट्रपति शासन लागू करने या कम से कम मुख्यमंत्री बदलने की मांग जोर पकड़ रही है। केंद्र सरकार द्वारा किए जा सकने वाले ये दो सबसे स्पष्ट हस्तक्षेप प्रतीत होते हैं, लेकिन फिर भी वह हेमलेट जैसी दुविधा में फंसी हुई हैः कार्रवाई करें या न करें? क्या यह टालमटोल है? नीतिगत पक्षाघात है? उदासीनता है? या फिर केंद्र को यह नहीं पता कि आगे क्या करना है?

यह सब खिचड़ी जैसा लगता है। यह तेज़ी से स्पष्ट होता जा रहा है कि भाजपा मणिपुर की नब्ज़ पर पूरी तरह से पकड़ नहीं बना पा रही है और वह इस बात को लेकर असमंजस में है कि क्या किया जाए। उदाहरण के लिए छह पुलिस थानों में AFSPA लगाने का जल्दबाजी में उठाया गया कदम एक नए जातीय मंथन को जन्म दे रहा है। 14 नवंबर को AFSPA को फिर से लागू किया गया। तीन दिन बाद मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने केंद्र को पत्र लिखकर इसे वापस लेने की मांग की, लेकिन गुरुवार को मणिपुर विधानसभा में सभी 10 कुकी विधायकों, जिनमें सात भाजपा विधायक भी शामिल थे, ने मांग की कि राज्य के सभी 60 पुलिस स्टेशनों में AFSPA लागू किया जाए, जिनमें 13 ऐसे भी हैं जो अभी भी इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। उनका कहना है कि वह चाहते हैं कि इस कानून को बढ़ाया जाए, ताकि अधिकारी पिछले साल 3 मई को राज्य के शस्त्रागारों से चुराए गए लगभग 6 हजार हथियारों की तलाश कर उन्हें जब्त कर सकें, जब राज्य में अराजकता फैल गई थी।

ऐसा लगता है कि भाजपा यह भूल गई है कि मणिपुर में AFSPA का इतिहास काला है। 1958 में उग्रवाद से निपटने के लिए इसे लागू किए जाने के बाद से ही विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं- शुरुआत में नगा-बहुल जिलों में और फिर 1980 में पूरे मणिपुर में। जुलाई 2004 में नाटकीय विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुए, जब 32-वर्षीय महिला थंगजाम मनोरमा के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और फिर सेना द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। चार साल पहले, 28-वर्षीय महिला इरोम शर्मिला ने AFSPA के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की थी, जिसे उन्होंने आखिरकार अगस्त 2016 में खत्म किया। 2022-23 में मणिपुर के बड़े हिस्से में इस कानून को वापस ले लिया गया।

मणिपुर से कैसे निपटा जाए, इस पर स्पष्टता की कमी पिछले मई में तब देखने को मिली, जब केंद्र ने इस बात पर असमंजस में था कि अनुच्छेद-355 लगाया जाए या नहीं। मीडिया खबरों में व्यापक रूप से भिन्नता थी, जिसमें एक वर्ग ने दावा किया कि इसे लगाया गया था, जबकि दूसरे ने दावा किया कि ऐसा नहीं था। कर्नाटक हाई कोर्ट के एक वकील द्वारा आरटीआई दायर करने के बाद आखिरकार जून में गृह मंत्रालय ने कहा कि – अस्पष्टता के लिए पूरे अंक - मंत्रालय के सीपीआईओ के पास 'जनवरी 2023 से जून 2023' की अवधि के लिए ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

अगर इसे उस समय लगाया गया होता, तो अनुच्छेद 355 काम कर सकता था। दूसरी ओर, छह पुलिस थाना क्षेत्रों में AFSPA को फिर से लागू करने का केंद्र का नवीनतम कदम गंभीर रूप से उलटा पड़ सकता है।

भाजपा की हरकतें चुनावी लाभ से प्रेरित हैं और मणिपुर उसकी प्राथमिकताओं की सूची में नहीं है। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार वहां सुरक्षित रूप से स्थापित है। सहयोगी दल नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी) ने कहा है कि वह बीरेन सिंह सरकार से समर्थन वापस ले रही है, लेकिन भाजपा ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। एनपीपी या यहां तक कि उसके सात कुकी विधायकों के बिना भी उसके पास संख्या है, जो मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ लगातार मुखर हो रहे हैं। कांग्रेस ने इस जून में मणिपुर में संसदीय सीटें जीतीं, लेकिन वहां केवल दो सीटें हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस भाजपा से बेहतर जानती है कि मणिपुर में आगे क्या करना है। इसके लिए श्रेय की बात यह है कि कम से कम राहुल गांधी ने राज्य का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। गांधी के दौरे ने कांग्रेस को आम चुनावों में राज्य में क्लीन स्वीप करने में मदद की, लेकिन अब देश के गृह मंत्री रहे पी चिदंबरम द्वारा किए गए एक ट्वीट ने पार्टी को बहुत शर्मिंदा कर दिया है, जिसे बाद में हटा दिया गया। उन्होंने मणिपुर की क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग की थी। कांग्रेस के राज्य नेतृत्व ने सार्वजनिक रूप से उनकी निंदा की है और मांग की है कि पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करे।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

सभापति ने कहा- आप अनुभवी, सदन की मर्यादा रखें; खड़गे बोले- मुझे मत सिखाइए

- राज्यसभा में धनखड़-खड़गे के बीच हुई जमकर बहस
- सदन का पहला दिन रहा हंगामेदार

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद के शीतकालीन सत्र का सोमवार को पहला दिन था। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बहस हुई। दरअसल धनखड़ ने खड़गे से कहा कि हमारे संविधान को 75 साल पूरे हो रहे हैं। उम्मीद है आप इसकी मर्यादा रखेंगे।

इस पर खड़गे ने जवाब दिया कि इन 75 सालों में मेरा योगदान भी 54 साल का है, तो आप मुझे मत सिखाइए। इस पर धनखड़ ने कहा- मैं आपको इतना सम्मान देता हूं और आप ऐसा बोल रहे हैं। मुझे दुख पहुंचा है। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर लोकसभा की कार्यवाही भी पूरी नहीं हो सकी। विपक्ष के नेता अडाणी मुद्दे पर हंगामा करते रहे। सदन को 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बार सत्र में अडाणी, मणिपुर हिंसा और ट्रेन दुर्घटनाओं पर हंगामे के आसार हैं। अमेरिका की न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट ने गौतम अडाणी पर सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को लगभग 2,200 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश का आरोप लगाया है।

टीएमसी सांसद बोले- वक्फ बोर्ड पर जल्दबाजी में रिपोर्ट नहीं दे सकते

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, हमने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला से मुलाकात की है। जेपीसी अध्यक्ष हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। जल्दबाजी में रिपोर्ट नहीं दी जा सकती। स्पीकर ने कहा कि वह हमारी भावनाओं का सम्मान करते हैं और वह कमेटी का कार्यकाल बढ़ाएंगे, सभी की बात सुनी जाएगी। ओम बिड़ला से विपक्ष के कई नेताओं ने मुलाकात की।

पीएम मोदी बोले-

मुट्ठी भर लोग हुड़दंगबाजी से संसद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं

नईदिल्ली (एजेंसी)। 2024 का अंतिम कालखंड चल रहा है। संसद का ये सत्र कई प्रकार से विशेष है। कल संविधान सदन में सभी मिलकर संविधान के 75 साल पूरे

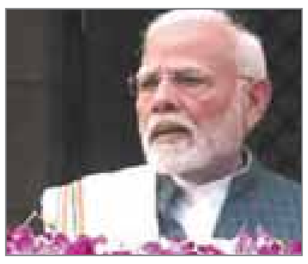

होने पर उत्सव का मिलकर आगाज करेंगे। संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय एक-एक बिंदु पर चर्चा की। तब जाकर ऐसा उत्तम दस्तावेज हमें मिला। इसकी महत्वपूर्ण इकाई है हमारी संसद। हमारे सांसद भी, संसद भी। संसद में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में योगदान दें। दुर्भाग्य से मुट्ठी भर लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए संसद को हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। जनता उन्हें देखती है फिर सजा देती है। मुट्ठी भर लोग हुड़दंगबाजी से संसद को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं।

देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुँचे, शाह से मिलेंगे

- सीएम कौन होगा अभी संशय बरकरार
आदित्य शिवसेना ठाकरे के नेता चुने गए

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा, इसके ऐलान पर अभी संशय बना हुआ है। अजीत पवार ने वैसे तो फडवणीस का समर्थन कर दिया है। सोमवार को देवेंद्र फडणवीस दिल्ली रवाना हो गए थे। और अमित शाह से मिलकर स्थिति साफ करेंगे। शायग इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाए। भाजपा से जुड़े सूत्रों का दावा है मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम तय हो माना जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजे आने के

बाद, 26 नवंबर विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। दिल्ली में बैठक के बाद ही तय होगा कि कौन होगा अगला सीएम।

मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तय हुआ है : मीडिया सूत्र

महायुति सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर सकती है। मीडिया के सूत्रों के मुताबिक, 1 मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तय हुआ है। महायुति की पार्टियों में हर 6-7 विधायक पर एक मंत्री पद का फॉर्मूला भी फाइनल हुआ है। इस हिसाब से भाजपा के 22-24, शिंदे गुट के 10-12 और अजित गुट के 8-10 विधायक मंत्री बन सकते हैं।

दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री में हुई बैठक में आदित्य ठाकरे को विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में पार्टी का संयुक्त नेता चुना गया है। भास्कर जाधव को शिवसेना (बीटी) के विधायक दल का नेता और सुनील प्रभु को चीफ व्हिप चुना गया है।

सुप्रभात

संविधान की शान निराली,
हम निज गौरव पाये हैं।
सम्प्रभु हम, है राज हमारा,
अंतर्मन मुस्काये हैं।।
कुर्बानी ने नग़मे गाये,
आज़ादी का वंदन है।
ज़ज़्बातों की बगिया महकी,
राष्ट्रधर्म-अभिनंदन है।।
संविधान की छटा निराली,
आकर्षण घिर आये हैं।
सम्प्रभु हम, है राज हमारा,
अंतर्मन मुस्काये हैं।।
संविधान में अधिकारों की,
बातों ने हर दिल जीता।
सप्त दशक का सफ़र सुहाना,
हर दिन है सुख में बीता।।
संविधान की गति-मति के तो,
पैमाने नित भाये हैं।
सम्प्रभु हम, है राज हमारा,
अंतर्मन मुस्काये हैं।।
जीवन हुआ सुवासित सबका,
जन-गण-मन का गान है।
हमने जो पाया है उस पर,
हम सबको अभिमान है।।
संविधान के कारण ही हम,
विजय नित्य पा पाये हैं।
सम्प्रभु हम, है राज हमारा,
अंतर्मन मुस्काये हैं।।

- प्रो. डॉ. शरद नारायण खरे

मुख्यमंत्री का लंदन में भारतीय उच्चायुक्त एवं प्रवासी भारतीयों ने किया आत्मीय स्वागत

विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने मुख्यमंत्री यूके और जर्मनी की विदेश यात्रा पर

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का लंदन पहुंचने पर यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त श्री विक्रम के दोराईस्वामी और प्रवासी भारतीयों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव फरवरी में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में विदेशी निवेशकों को मध्यप्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए आमंत्रित करने के लिए इंग्लैंड और जर्मनी प्रवास पर हैं। अपने 6 दिवसीय विदेशी प्रवास के दौरान वे उद्योगपतियों से मुलाकात कर उन्हें मध्यप्रदेश आने का न्यौता देंगे। मुख्यमंत्री के साथ अधिकारियों का उच्च स्तरीय दल भी विदेश प्रवास पर है।

वैश्विक निवेश को मिलेगा प्रोत्साहन- मुख्यमंत्री डॉ. यादव की यात्रा का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश को औद्योगिक हब बनाने के साथ ही हर प्रकार के उद्योग को आमंत्रण के साथ मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाईयां देने और वैश्विक निवेश को आकर्षित करना है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दी ब्रिटिश संसद परिसर में पुष्पांजलि

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज यूके में प्रवास के दौरान ब्रिटिश संसद परिसर का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संसद परिसर में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती सीमा यादव, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र सिंह और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

विश्व पटल पर होगा मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की यह निवेश यात्रा राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने तथा विश्व पटल पर उद्योग के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी। यह यात्रा निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखी जा रही है, जो प्रदेश में निवेशकों का विश्वास को मजबूती और औद्योगिक विकास को गति प्रदान करेगी। इससे प्रदेश में एक समृद्ध औद्योगिक वातावरण का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश के महानगरों से औद्योगिक निवेश को आमंत्रित करने के लिए उन्होंने कलकत्ता, बेंगलोर, मुम्बई और कोयम्बटूर में रोड शो आयोजित कर उद्योगपतियों से मुलाकात की थी। विदेश यात्रा का उद्देश्य भारतीय निवेशकों के साथ ही विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करना भी है।

अडानी समूह को लग रहे हैं झटके पे झटके

- फ्रांस की दिग्गज एनर्जी कंपनी टोटलएनर्जीज अडानी ग्रुप कंपनियों में कोई नया पैसा नहीं लगाएगी
- यह तब तक रहेगा जब तक गौतम अडानी पर लगे आरोप साफ नहीं हो जाते

नई दिल्ली (एजेंसी)। फ्रांस की दिग्गज एनर्जी कंपनी टोटलएनर्जीज ने बड़ा ऐलान किया है। सोमवार को उसने कहा कि वह अडानी समूह की कंपनियों में अपने निवेश के तहत कोई नया पैसा नहीं लगाएगी। ऐसा तब तक रहेगा जब तक गौतम अडानी पर लगे रिश्वतखोरी के आरोप साफ नहीं हो जाते। एनर्जी कंपनी ने कहा कि उसे भ्रष्टाचार की जांच के बारे में पता नहीं था। टोटलएनर्जीज अरबपति गौतम अडानी के व्यापारिक साम्राज्य में सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक है। इसने पहले समूह की रिन्यूएबल एनर्जी वेंचर अडानी ग्रीन एनर्जी और सिटी गैस यूनिट अडानी टोटल गैस में हिस्सेदारी ली थी। फ्रांसीसी फर्म ने बताया है कि उसे अमेरिकी अधिकारियों की ओर से गौतम अडानी और दो अन्य अधिकारियों पर आरोपों के बारे में पता चला है।

- **अडानी ग्रुप कंपनियों में बड़ी हिस्सेदार है टोटलएनर्जीज-** टोटलएनर्जीज के पास अडानी ग्रीन एनर्जी में 19.75 फीसदी हिस्सेदारी है। यह गौतम अडानी के नेतृत्व वाले भारतीय समूह की रिन्यूएबल एनर्जी इकाई है। इसके पास तीन संयुक्त उद्यम कंपनियों में 50 फीसदी हिस्सेदारी भी है जो एईजीएल के साथ सौर और पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन करती हैं।
- **तेलंगाना ने अडाणी का 100 करोड़ डोनेशन ठुकराया-** तेलंगाना सरकार ने अडाणी ग्रुप के 100 करोड़ रुपए डोनेशन का ऑफर ठुकरा दिया है। यह डोनेशन यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए दिया जा रहा था। सोमवार को यह जानकारी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 23 °c
न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ मंगलवार, 26 नवंबर 2024

> जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।
>
> चाणक्य नीति

संक्षिप्त समाचार

संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष-समाजवादी शब्द हटाने की मांग खारिज

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। 22 नवंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।

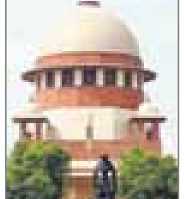

सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा– इन शब्दों को संविधान में 42वें संशोधन (1976) के जरिए शामिल किया गया था और ये संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा हैं। बेंच ने कहा– संविधान में दर्ज 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी विशेषताओं को बताते हैं। इन्हें हटाना उचित नहीं है।

प्रदूषण कम होने तक ग्रैप-4 लागू : सुप्रीम कोर्ट

पूछा- 2 दिन में बताएं दिल्ली में जल्द स्कूल कैसे खुलेंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा– प्रदूषण कम होने तक दिल्ली में ग्रैप–4 लागू रहेगा। साथ ही एयर क्वालिटी कमिशन से पूछा कि 2 दिन में बताएं दिल्ली में जल्द स्कूल कैसे खुलेंगे।

जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि सिर्फ तकनीक के इस्तेमाल को बेहतर बनाने से न्याय की गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा।

बांग्लादेश में इस्कान के चिन्मय कृष्ण दास प्रभु गिरफ्तार

हिंदुओं के पक्ष में निकाली थी रैली

ढाका (एजेंसी)। बांग्लादेश में हिंदू नेता और इस्कान के सदस्य चिन्मय कृष्ण दास प्रभु को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने फर्जी राजद्रोह मामले में उन्हें ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है।

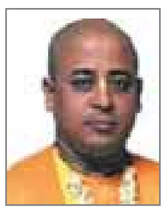

जानकारी के अनुसार पुलिस उन्हें विदेश की यात्रा नहीं करने देना चाहती थी। चिन्मय प्रभु लगातार बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करते आए हैं और हिंदुओं के समर्थन में हाल ही में रैली भी निकाली थी।

चुनाव से पहले आप सरकार का ऐलान

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आप सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन स्कीम को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। स्कीम में 80 हजार नए बुजुर्गों को और जोड़ा गया है।

म.प्र. में पेपर लीक पर आजीवन कारावास,1 करोड़ जुर्माना

नकल करने पर भी होगी सजा; सरकार बदलेगी 1937 का परीक्षा कानून

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में अब किसी ने पेपर लीक किया तो उसे आजीवन कारावास और 1 करोड़ रु. तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। कोई नकल करता पकड़ा जाएगा तो वह जेल नहीं जाएगा, लेकिन अगले एक साल तक परीक्षा नहीं दे सकेगा। दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार पेपर लीक और परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए कड़ा कानून लाने जा रही है।

इसके लिए 1937 में बने परीक्षा कानून में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। संशोधित कानून का ड्राफ्ट स्कूल शिक्षा विभाग ने तैयार कर लिया है। यह ड्राफ्ट परीक्षण के लिए विधि विभाग को भेजा गया है। इसके बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकार की कोशिश है कि इस कानून को शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में पारित कराकर लागू किया जाए।

दरअसल, इसी साल जून में नीट पेपर लीक का मुद्दा गर्माया था। इसके बाद ही राज्य सरकार ने कानून में संशोधन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को ड्राफ्ट बनाने के लिए कहा था। विभाग ने बाकी राज्यों में लागू कानून का अध्ययन कर ड्राफ्ट को वरिष्ठ सचिव समिति के सामने रखा था।

इसी बीच केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 के नियम जारी कर राज्यों को भेज दिए। इसके बाद इस कानून को समग्रता से तैयार करने निर्देश दिए गए। नए कानून के ड्राफ्ट में नकल रोकने के लिए किस तरह के प्रावधान किए गए हैं, इसके दायरे में कौन-कौन आएगा?

नए कानून की जरूरत क्यों?– मप्र का जो मौजूदा कानून है, उसमें जुर्माने और सजा का प्रावधान मामूली है। हालांकि पिछले साल 10वीं और 12वीं परीक्षा के दौरान कथित पेपर लीक की घटनाएं सामने आने के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल की कार्यपालिका समिति ने 10 साल की सजा और दस लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया था।

शिक्षाविद् प्रोफेसर भागीरथ कुमरावत कहते हैं कि इसी साल नीट परीक्षाओं के पेपर लीक होने के बाद केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 लागू किया। ये कानून केंद्र सरकार की परीक्षाओं पर लागू है। हर राज्य अलग-अलग परीक्षाओं का आयोजन करता है। केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है उसके नियम राज्यों को भेजे गए हैं, ताकि वे अपने हिसाब से कानून बना सकें।

प्रिंटिंग प्रेस को लेकर होंगे ये नियम

- पेपर सेट करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।
- पेपर लाने ले जाने के लिए बक्सों में छेड़छाड़ रोधी मल्टी लेवल पैकेजिंग होगी।
- पेपर छापने वाली एजेंसी का एग्जाम कंट्रोलर द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा।
- प्रिंटिंग प्रेस में आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। सभी के पास पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा।
- पेपर की छपाई के दौरान स्मार्टफोन और कैमरा ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
- प्रेस के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और इसकी रिकॉर्डिंग 1 साल तक सुरक्षित रखी जाएगी।

नए कानून के प्रावधान– मप्र सरकार के प्रस्तावित नए कानून के दायरे में परीक्षाओं से जुड़े सभी व्यक्ति, अधिकारी-कर्मचारी, संस्थाएं रहेंगी। परीक्षा केंद्र, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी या कोई व्यक्ति जो पेपर लीक या किसी गड़बड़ी में शामिल पाया जाता है तो उसकी सीधे जवाबदारी तय होगी। इसमें एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। आरोपी की प्रॉपर्टी भी अटैच या जब्त करने का प्रावधान है।

स्टूडेंट की बजाय संगठित गिरोह दोषी माना जाएगा– परीक्षार्थी यदि नकल करता पाया जाता है या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करता है तो उसे जेल नहीं होगी, लेकिन उसे निकाल दिया जाएगा। वह एक साल तक परीक्षा नहीं दे सकेगा, हालांकि उसके प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने पर रोक नहीं रहेगी। परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी के लिए स्टूडेंट से अधिक संगठित अपराध, माफिया और इसमें शामिल लोगों को अधिक दोषी माना जाएगा।

डीएसपी या सहायक पुलिस आयुक्त करेंगे जांच

- नए कानून में प्रावधान है कि प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी कोई भी गड़बड़ी मिलने पर उसकी जांच डीएसपी या सहायक पुलिस आयुक्त करेंगे।
- केंद्र सरकार ये जांच केंद्रीय एजेंसी करा सकती हैद्य इस परीक्षा में प्रतिभागी की जगह अन्य कोई शामिल होता है तो इसे अनैतिक माना जाएगा।
- इस कानून के तहत एग्जाम सेंटर के लिए सरकारी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों को प्राथमिकता दी जाएगी। परीक्षा प्रश्न-पत्र में एक गुप्त कोड होगा।

परीक्षा केंद्र प्रभारी और स्टाफ पर मोबाइल की पांबदी

- प्रस्तावित कानून के तहत परीक्षा केंद्रों के प्रभारी और स्टाफ पर मोबाइल ले जाने की पाबंदी रहेगी।
- अगर कोई केंद्र अध्यक्ष, सहायक केंद्र अध्यक्ष या पर्यवेक्षक मोबाइल का इस्तेमाल करते पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
- परीक्षा केंद्रों के को-ऑर्डिनेटर, प्रभारी और क्षेत्रीय अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भी इसमें प्रावधान किए गए हैं।
- किसी भी जिम्मेदार के जानबूझकर लापरवाही करने से पेपर लीक होता है या लीक होने की आशंका से परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई होगी।
- ब्लैक लिस्ट हो सकती है सर्विस प्रोवाइड कंपनी।
- सर्विस प्रोवाइड यानी वह एजेंसी या कंपनी जो परीक्षा के लिए कम्प्यूटर से लेकर अन्य संसाधन या सिस्टम उपलब्ध कराए।
- सर्विस प्रोवाइड यदि गड़बड़ी को तुरंत पुलिस या परीक्षा कराने वाली एजेंसी को नहीं बताता, तो वो भी दोषी होगा।
- सर्विस प्रोवाइडर परीक्षा केंद्र को स्वेच्छा से नहीं बदल सकेंगे।
- सर्विस प्रोवाइडर गड़बड़ी में शामिल पाए गए तो ब्लैक लिस्ट किए जाएंगे।
- यह साबित हो जाए कि परीक्षा में गड़बड़ी के लिए सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ा व्यक्ति या पदाधिकारी जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा।

पेपर लीक करने वाले गिरोह से वसूली जाएगी लागत

यदि परीक्षा प्रभावित होती है या दोबारा आयोजित करने की स्थिति बनती है तो उस पर आने वाले वित्तीय भार को पेपर लीक करने वाले गिरोह से वसूल किया जाएगा और उनकी संपत्ति कुर्क की जा सकेगी। किसी की जगह बैठकर परीक्षा देने वाले सॉल्वर भी इसके दायरे में लाए जा रहे हैं। इसमें कॉपी, अवॉर्ड शीट, नंबर रजिस्टर, मार्क शीट में गड़बड़ी भी शामिल है।

संभल हिंसा पर कमिश्नर का दावा

पुलिस की नहीं, तमंचे की गोली से 4 मौत

सपा सांसद जिआउर्रहमान बर्क समेत पांच पर एफआईआर, संभल में हिंसा भड़काने का आरोप

लखनऊ/ संभल (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हिंसा भड़काने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संभल लोकसभा के सांसद जिआउर्रहमान बर्क, सदर विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल और अन्य पांच लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। सभी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है। वहीं संभल हिंसा पर कमिश्नर का दावा पुलिस की नहीं, तमंचे की गोली से 4 मौत हुई थी।

हालांकि, अधिकारियों के द्वारा रिपोर्ट की पुष्टि अभी नहीं की गई है, लेकिन कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं, संभल में हुए बवाल के बाद पुलिस ने जामा मस्जिद के सदर जफर अली समेत 20 से अधिक लोगों को हिरासत लिया है और 400 अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की है।

सड़कों पर पसरा सन्नाटा, बाजार बंद, डीआईजी ने किया फ्लेग मार्च – जिले में हुए बवाल के बाद पूरी रात पुलिस पैदल गश्त करती रही। उच्चाधिकारियों ने गश्त का नेतृत्व किया। जहां-जहां बवाल में आगजनी और पथराव हुआ था, वहां पर विशेष फोकस किया गया और भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। साथ ही लगातार संदिग्ध लोगों पर भी नजर रखी जा रही है।

सोमवार सुबह भी बाजार बंद थे– उधर सोमवार सुबह भी बाजार बंद दिखाई दिए। साथ ही लोग अपने घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सुबह में डीआईजी मुनिराज ने पुलिस बल के साथ सड़कों पर फ्लैग मार्च किया है। इसके अलावा डीएम के द्वारा घोषित किए गए अवकाश के बाद स्कूल कॉलेज के लिए बच्चे नहीं निकले।

संभल हिंसा में पांच की मौत

संभल में रविवार को अधिकारियों से चार लोगों की मृत्यु होने की पुष्टि की है। एक अन्य की मौत होने की बात भी कही जा रही है, लेकिन उसके स्वजन ने कानूनी कार्रवाई नहीं की है। पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। 19 नवंबर को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कोर्ट में मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया था।

कोर्ट ने उसी दिन सर्वे का आदेश दिया और वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश राघव को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया था। 19 को ही मस्जिद में वीडियोग्राफी कराई गई थी। इसके बाद एडवोकेट कमिश्नर ने रविवार को दूसरे चरण की वीडियो ग्राफी कराई। इसी दौरान बवाल हो गया था।

सीएम योगी ने पूछा-कौन कहता है हम बंटे हैं,ये कथा जवाब

प्रदीप मिश्रा ने कहा- सीएम के नारे ने यूपी-महाराष्ट्र में जीत दिलाई

वाराणसी (एजेंसी)। वाराणसी में सीएम योगी पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में पहुंचे। व्यास पीठ पं. प्रदीप मिश्रा के पास ही योगी का आसन लगा। सीएम योगी ने कहा- कौन कहता है कि हम आपस में बंटे हैं। कहां जातिवाद है, कहां संप्रदाय का वाद है, कहां उपासना विधि का विवाद है...हम तो एक होकर इस कथा के जरिए राष्ट्रवाद में खुद को राष्ट्र के लिए समर्पित कर रहे हैं। एक धर्म योद्धा की तरह...ये कथा इसका एक उदाहरण है।

योगी के कथा में शामिल होने पर प्रदीप मिश्रा ने कहा- मुख्यमंत्री योगी का नारा पूरे चुनाव में गूंजता रहा। 'बंटोगे तो कटोगे' नारे ने महाराष्ट्र और यूपी के चुनाव में भाजपा को जीत दिलाई।

योगी के वाराणसी पहुंचने पर वकीलों ने हंगामा किया

सीएम योगी वाराणसी पहुंचे तो वकीलों ने सोमवार दोपहर हंगामा कर दिया। स्टांप मंत्री रविंद्र जायसवाल के विरोध में उतरे वकीलों ने नारेबाजी की। योगी का घेराव करने जा रहे जा रहे वकीलों को कचहरी का गेट बंद करके पुलिस ने रोका।

योगी बोले-जाति के नाम पर बांटने वालों को ये कथा जवाब

सीएम योगी ने कहा - इस कथा को सिर्फ भक्त ही नहीं सुन रहे हैं, महादेव भी सुन रहे हैं। बाबा भैरवनाथ, काल भैरव, मां गंगा और अन्न-पूर्णा भी सुन रही हैं। यह सब उन लोगों के मुंह पर एक जवाब है, जो हमें जाति के नाम पर बांट रहे हैं, उनकी आंखों को खोलने के लिए कथा पर्याप्त है।

प.बंगाल गवर्नर मूर्ति विवाद

राजभवन बोला- बोस ने अपनी मूर्ति का इनॉगरेशन नहीं किया

कोलकता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस से जुड़े मूर्ति विवाद को लेकर सोमवार को राजभवन ने बयान जारी किया। राज्यपाल ऑफिस ने कहा- मीडिया रिपोर्ट में राज्यपाल बोस द्वारा अपनी प्रतिमा का अनावरण करने का जो दावा किया जा रहा है।

वह गलत है। यह उन्हें बदनाम करने की साजिश है। दो सदस्यीय पैनल इसकी जांच करेगा।

दरअसल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने 23 नवंबर को अपने कार्यकाल के दो साल पूरे किए थे। इस मौके पर उनकी एक तस्वीर सामने आई थी। जिसमें वह अपनी एक मूर्ति के साथ खड़े थे।

8 राज्यों में कोहरा, म.प्र.-राजस्थान में तापमान 7 डिग्री से नीचे

- बिहार के पुर्णिया में विजिबिलिटी-100 मीटर, हिमाचल में सीजन की पहली बर्फबारी

नई दिल्ली/भोपाल/जयपुर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में बर्फबारी के कारण पहले उत्तर भारत के राज्यों में ठंड बढ़ी थी। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो गया है।

मध्य प्रदेश के पचमढ़ी, नर्मदापुरम और राजस्थान के माउंट आबू में तापमान 7 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। तीनों राज्यों के कई शहरों में पिछले 3 दिन से तापमान 10 डिग्री के नीचे दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि सोमवार सुबह इन तीन राज्यों के अलावा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार में भी कोहरा छाया रहेगा। कोहरे के कारण बिहार के पुर्णिया में विजिबिलिटी घटकर 100 मीटर रह गई। हिमाचल प्रदेश में सीजन की पहली बर्फबारी हुई।

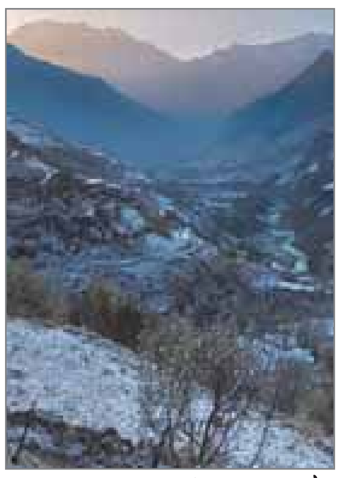

म.प्र.-राजस्थान में ठंड का दौर तीन दिन और– मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि पहाड़ों पर बर्फ पिघलने के बाद वहां से आई बर्फीली हवा और सतह से 12 किमी ऊपर चल रही सर्द हवा के कारण मध्य प्रदेश और राजस्थान में ठंड पड़ रही है।

झांसी में धीरेंद्र शास्त्री पर बुलडोजर से फूलों की बारिश

चोटी से रथ को खींच रहा भक्त, बोले– कुछ लोग धमका रहे, उलझना नहीं, संजय दत्त, ग्रेट खली भी पहुंचे

झांसी (नप्र)। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की 'सनातन हिंदू एकता' पदयात्रा आज यानी सोमवार को यूपी में प्रवेश कर चुकी है। मध्य प्रदेश बॉर्डर से पदयात्रा यूपी के झांसी में देवरी गांव पहुंची। यहां बुलडोजर से फूल बरसा कर पदयात्रा का स्वागत किया गया।

देवरी गांव में पं. धीरेंद्र शास्त्री ने मीडिया से बात की। पदयात्रा को लेकर मिल रही धमकियों के सवाल पर शास्त्री ने कहा- ये सब प्रायोजित तरीके से चल रहा है। जो लोग देश में वैमनस्यता चाहते हैं वो ऐसा कर रहे हैं। अगर हम ऐसे लोगों की बातों में उलझ जाएंगे तो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। सनातन हिंदू एकता के लिए हम निकले हैं। सबको एकजुट करके रहेंगे।धीरेंद्र शास्त्री से मिलने के लिए रेसलर द ग्रेट खली और बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त पहुंचे। संजय दत्त 30 मिनट तक सड़क पर बैठे दिखे। चाय की चुस्की लीं।

पदयात्रा भदरवारा होते हुए मऊरानीपुर पहुंचेगी। यहां पर ग्रामोदय में रात्रि विश्राम होगा। यात्रा को लेकर पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं। 1000 से ज्यादा फोर्स को ड्यूटी में तैनात किया गया है।सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त भी शामिल हुए। उन्होंने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से आशीर्वाद लिया।

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा- संभल का सत्य सामने आना चाहिए

पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने संभल में सर्वे टीम पर हुए हमले के मामले में कहा कि जो सत्य हो उसे निकल कर आना चाहिए। इसी प्रकार के उपद्रवों से देश को बचाने के लिए ऐसी यात्राओं की आवश्यकता है।

पदयात्रा में द ग्रेट खली भी पहुंचे

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा में द ग्रेट खली पहुंच गए हैं। अभी पदयात्रा भदरवारा पहुंच चुकी है। जहां पर लंच चल रहा है। इसके बाद पदयात्रा मऊरानीपुर के लिए प्रस्थान करेगी।

एफटीए के सर्वे में भारत की रिपोर्ट सबसे अच्छी, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले- देश बन रहा ताकतवर

इंदौर। यूरेशियन ग्रुप (ईएजी) की 41वीं बैठक की शुरुआत सोमवार से ब्रिलियंट कंवेंशन सेंटर में शुरू हुई। स्वागत सत्र में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा भारत एक सनातन परंपरा वाला देश है, हमारे वेदों की ऋचाओं में लिखा है वसुधैव कुटुंबकम विश्व एक परिवार है। उन्होंने कहा- जब हम विश्व की बात करते हैं, तो हमारे मित्र देश हो या अन्य कोई भी देश हम हमेशा सहायता के लिए खड़ा रहते हैं। कोविड के दौरान पूरा विश्व संकट में था। उसे समय भारत एक ऐसा देश था, जिसमें सबसे पहले वैक्सीन बनाई। भारत ने अपने नागरिकों को वैक्सीन लगाने के साथ 100 देशों को वैक्सीन भेज कर सहायता भी की। भारत धीरे-धीरे ताकतवर बन रहा है। इससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हम विश्व में शांति के समर्थक हैं और विश्व शांति के प्रयास करेंगे।

विश्व की समस्याओं में आतंकवाद प्रमुख है- आज विश्व में जिस तरह की समस्याएं है, उसमें आतंकवाद प्रमुख है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के हर मंच से एक बात कहते हैं कि आतंकवाद किसी भी तरह का स्वीकार नहीं किया सकता। मंत्री

विजयवर्गीय ने साइबर क्राइम को सबसे बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि इस समय साइबर क्राइम की समस्या बढ़ रही है। दूर देश में बैठकर लोगों को लूटा जा रहा है। इस समस्या पर इस बैठक में बड़ा निष्कर्ष निकलेगा।

मंत्री विजयवर्गीय ने इएजी बैठक की मेजबानी का अवसर इंदौर को देने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने ईएजी के चेयरमैन का स्वागत करते हुए कहा कि हमारे युवा हुआ करते थे राजकपूर, चेयरमैन उनकी तरह दिखते हैं और यह राजकपूर के प्रसंशक भी है। इएजी के चेयरमैन यूरी चिंग ने ग्रुप की बैठक और एजेंडे की जानकारी दी।

टेरर फंडिंग की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण बैठक- सांसद शंकर लालवानी भारत सरकार की तरफ से सभी डेलीगेट का स्वागत करते हुए कहा कि यह बैठक मनी लांड्रिंग और टेरर फंडिंग की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। बॉर्डर पार से होने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाने सहित अन्य कई निष्कर्ष इस बैठक में निकलेंगे। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहां की यूरेशियन ग्रुप के सभी सदस्यों का देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में स्वागत हैं। इंदौरियन इस आयोजन को लेकर बड़े उत्साहित है। इंदौर हार्टबीट ऑफ इंडिया ही नहीं स्वच्छ सिटी और स्मार्ट सिटी भी है। कलेक्टर आशीष सिंह ने भी सभी का इंदौर में स्वागत किया।

पांच दिन होंगे अलग-अलग स्तर सत्र- ईएजी की 41वीं बैठक का आयोजन इंदौर में होने जा रहा है। पांच दिवसीय बैठक में प्रतिदिन अलग-अलग क्षेत्र में टेरर फंडिंग और मनी लांड्रिंग के साथ साइबर क्राइम जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। बैठक में 16 देश और 13 संगठन के प्रतिनिधि और एचओडी शामिल हो रहे हैं। भारत की तरफ से एचओडी के रूप में एडिशनल सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल शामिल होंगे।

सभी देशों में भारत की रिपोर्ट सबसे बेहतर- भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल ने बताया कि ईएजी की बैठक से पहले सभी बड़े देशों का एफटीए ओर ईएजी द्वारा वेल्यूशन किया गया था। इसमें भारत के अलावा अमेरिका, जर्मनी, कनाडा जैसे देश शामिल रहे। इनमें भारत की रिपोर्ट सबसे अच्छी आई है। भारत की इस रिपोर्ट पर पहले सत्र में आज चर्चा की जाएगी। इस रिपोर्ट को ईएजी में अपडेशन कराया जाएगा।

इंदौर में अपर मुख्य सचिव श्रीवास्तव ने ली समीक्षा बैठक

राजस्व महा अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन, तय बिन्दुओं के लक्ष्य पूरे करने के निर्देश

इंदौर। इंदौर जिले के प्रभारी तथा अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव ने आज इंदौर संभाग के सभी जिला कलेक्टर और जिला पंचायत सीओ की बैठक ली। बैठक में उन्होंने ग्रामीण विकास कार्यों की प्रगति, राजस्व प्रकरणों के निराकरण और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा संभागीय बैठक में दिए गए निर्देशों के परिपालन की जिले वार समीक्षा की। बैठक में संभागायुक्त दीपक सिंह, इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह सहित संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर और जिला पंचायतों के सीओ मौजूद थे। बैठक में संभागायुक्त दीपक सिंह, इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह सहित संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर और जिला पंचायतों के सीओ मौजूद थे। बैठक में अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव ने राज्य शासन के निर्देशानुसार चलाए जा रहे राजस्व महा अभियान 3.0 की प्रगति की विशेष रूप से समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। यह तय किया जाए कि इस अभियान का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। राजस्व महा अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों जैसे- सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, परम्परागत मार्गों के चिह्नांकन, नक्शे में बटांकन, आधार से खसरे की लिंकिंग, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन आदि की समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व महा अभियान के प्रत्येक बिन्दु के तय लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन सहित अन्य राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा भी की। निर्देश दिए गए कि राजस्व प्रकरणों का निराकरण तय समय सीमा में किया जाए। सीमांकन के लंबित प्रकरणों के निराकरण को विशेष प्राथमिकता दी जाए। श्रीवास्तव ने ग्रामीण विकास कार्यों की प्रगति की भी ?जिलेवार समीक्षा की। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण), मध्यप्रदेश आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत अभियान आदि की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्धारित लक्ष्यों को समय सीमा में पूरा किया जाए।

नए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का इंतजार

हॉकी टर्फ मैदान की तीन साल में सिर्फ बाउंड्रीवॉल बनी, फुटबॉल मैदान है ही नहीं, नेहरू स्टेडियम जर्जर

इंदौर। देश को क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस जैसे खेलों में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी देने वाले इंदौर शहर में इंटरनेशनल स्तर के खेलों के आयोजन के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। होलकर स्टेडियम में दर्शक कैपेसिटी क्षमता कम होने से आईपीएल व इंटरनेशनल जैसे मैच इंदौर को नहीं मिल पा रहे हैं, जबकि आईपीएल की टीमें इंदौर को होम ग्राउंड बनाने की इच्छा जता चुकी हैं। होलकर स्टेडियम की मौजूदा क्षमता 25 हजार दर्शकों की है, जबकि आईपीएल व इंटरनेशनल मैचों के लिए 50 से 75 हजार दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम होना चाहिए। वहीं हॉकी, फुटबॉल जैसे खेलों के लिए स्टेडियम तो दूर, खेलने के लिए राष्ट्रीय स्तर के मैदान ही नहीं हैं। 10 साल से शहर में नए अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने के लिए कवायद चल रही है, लेकिन यह कागजों तक ही सीमित रह जाती है, जिसका खामियाजा शहर के खिलाड़ियों व शहरवासियों को उठाना पड़ रहा है। हॉकी टर्फ के लिए काम शुरू हुए तीन साल हो गए, लेकिन अब तक सिर्फ बाउंड्रीवॉल ही बन सकी है। आ

इंदौर में नाले में मिला लापता बच्ची का शव : गुस्साए परिजन और रहवासियों ने किया चक्काजाम, गुजरात से नाना-नानी के घर आई थी

इंदौर। इंदौर में 6 साल की लापता बच्ची का शव सोमवार को नाले में मिला है। बच्ची माता-पिता के साथ गुजरात से इंदौर के राजेंद्र नगर आई थी। शनिवार को परिवार ने बच्ची के गुम होने की शिकायत थाने में की थी। शव मिलने के बाद गुस्साए परिजन और स्थानीय लोगों ने गमले वाली पुलिया पर चक्काजाम कर दिया। लोग निगम प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। उनका आरोप है कि पुलिस के पास बाउंड्री वॉल बनाने के लिए कई आवेदन दिए गए, लेकिन बाउंड्री वॉल तैयार नहीं की गई। फिलहाल, यह साफ नहीं हुआ है कि बच्ची की मौत कैसे हुई। स्थानीय निवासी अनूप दुबे ने आरोप लगाया कि पिछले कई सालों से तालाब पर बाउंड्री वॉल बनाने के लिए नगर निगम प्रशासन को ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई।

3-4 दिन पहले ही नानी के घर आई थी बच्ची

तीन से चार दिन पहले ही जीवन मीणा परिवार के साथ इंदौर आए थे। उज्जैन में वो एक शादी में भी शामिल हुए थे। शनिवार शाम को जीवन अपने परिवार के साथ इंदौर के राजेंद्र नगर थाना पहुंचे। उन्होंने अपनी 6 साल की बच्ची लक्षिका के गुम होने की शिकायत दर्ज कराई।ॉ पुलिस को जीवन मीणा ने बताया था कि वे गुजरात के सुरेंद्र नगर में एक फार्मा कंपनी में काम करते हैं। पत्नी और दो बच्चों को लेकर शिव सागर कॉलोनी में रहने वाले नाना-नानी से मिलने इंदौर आए थे। दोपहर में पत्नी शालिनी पास के ही ब्यूटी पार्लर गई थी।

लक्षिका

पत्नी ने कहा- बेटी को बाल कटवाने भेजो

दोपहर करीब 1 बजकर 35 मिनट पर पत्नी शालिनी का कॉल आया कि बेटी को भेज दो। उस समय जीवन खाना खा रहे थे। उन्होंने शालिनी के चचेरे भाई ऋषि से बच्ची को उसकी मम्मी के पास छोड़ कर आने के लिए कहा। ऋषि ने लक्षिका को साथ ले जाने के लिए ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। आसपास के लोगों से उसके बारे में पूछा, लेकिन तब भी उसकी जानकारी नहीं लगी। काफी देर तक खोजने के बाद परिवार ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर बच्ची की तलाश शुरू कर दी थी। इस बीच सोमवार को बच्ची का शव मिला।

रहवासी बोले- हमें बच्ची का हत्यारा चाहिए- रहवासी सरोज पाठक ने बताया कि, बच्ची को किसी ने घर में रखा और नाले में लेकर जाकर फेंक दिया है। क्योंकि तीन दिन में बॉडी फूल जाती है। लेकिन बच्ची का बॉडी फूली नहीं थी। बच्ची के कपड़े फटे हुए हैं। हमें बच्ची का हत्यारा चाहिए।

एससीपी ने कहा- कचरे में मिला बच्ची का शव- एसीपी रुबीना मिजवानी के मुताबिक, सीसीटीवी फुटेज और डॉग स्क्वायड की मदद से हम यहां तक पहुंचे। इसके बाद एसडीआरएफ और नगर निगम टीम की मदद से सर्चिंग शुरू की। पोकलेन मशीन से कचरा हटाया गया। इसी कचरे में बच्ची का शव मिला। बच्ची अपने माता-पिता के साथ इंदौर में अपने नाना-नानी के घर शादी में आई थी।

ऑनलाइन गेमिंग के लिए लेता था उधार

सूदखोरों के पैसे न लौटा पाया तो खाया जहर, मौत

इंदौर। इंदौर में सूदखोरी से परेशान एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए पैसे उधार लिए थे। जो न चुका पाने की सूरत में आत्महत्या जैसा

खतरनाक कदम उठाया। युवक का इलाज तेजाजी नगर स्थित ट्रॉमा सेंटर में चल रहा था जहां सोमवार को उसकी मौत हो गई। इंदौर के ग्राम दतोदा में रहने वाले छोटू पिता परमानंद राठौर इंदौर के मुसाखेड़ी इलाके में किराए से रहता था। जहां पर उसके द्वारा ऑनलाइन गेम खेलने के लिए ब्याज पर रुपए उधार लिए थे। जिसको न चुकाने के कारण उसपर लगातार सूदखोर दबाव बना रहे थे। जिससे परेशान होकर युवक के द्वारा जहरीली वस्तु खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि जहर खाने के बाद युवक को उपचार के लिए तेजाजी नगर स्थित ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले में तेजाजी नगर पुलिस ने मर्ग कायम किया है। साथ ही इस पूरे प्रकरण की जांच भी पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है।

इंदौर एयरपोर्ट पर नया एटीसी टॉवर हुआ 42 करोड़ में तैयार, 120 फीट है ऊंचाई

इंदौर। नए साल में एटीसी की औपचारिक शुभारंभ करने की तैयारी की जा रही है। समारोह में केंद्रीय मंत्रियों को बुलाने की तैयारी भी की जा रही है। फिलहाल विमानतल पर 20 साल पुराने एटीसी से उड़ानों का संचालन किया जाता है। इंदौर के देवी अहिल्या बाई विमानतल पर नया एयर ट्रैफिक टॉवर तैयार हो चुका है। जल्दी ही इसका ट्रायल शुरू होगा। नए साल में नए एटीसी टॉवरों से ही उड़ानों के टेक आफ और लैंडिंग का संचालन होगा। सात मंजिला नए टॉवर का निर्माण 42 करोड़ रुपये में हुआ है। इसमें लगे आधुनिक उपकरणों की मदद से विमानों के उड़ान भरने और उतरने का संचालन और सुविधानजनक होगा। खासकर कोहरे और थोड़े खराब मौसम में भी विमान एयरपोर्ट पर उतर सकेंगे। नए साल में एटीसी की औपचारिक शुभारंभ करने की तैयारी की जा रही है। समारोह में केंद्रीय मंत्रियों को बुलाने की तैयारी भी की जा रही है। फिलहाल विमानतल पर 20 साल पुराने एटीसी से उड़ानों का संचालन किया जाता है। लंबे समय से नए एटीसी टॉवर की जरुरत महसूस हो रही थी। वर्ष 2022 में तत्कालीन केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसके निर्माण की मंजूरी दी थी। सात मंजिला टॉवर 120 फीट ऊंचा है। मौजूदा टॉवर से इसकी ऊंचाई 20 मीटर ज्यादा है और ज्यादा आधुनिक भी है।

इंदौर में सीएम कन्यादान योजना के समारोह में हंगामा, दूल्हे ने प्रेमिका को पीटा

दुल्हन और प्रेमिका में मारपीट, बाल नोंचे-चोटी खींची

इंदौर। इंदौर में शुक्रवार को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के शादी समारोह में हंगामा मचाने वाली कथित प्रेमिका और दुल्हन के बीच मारपीट का वीडियो शनिवार को सामने आया है। दोनों ने शादी के मंडप में एक-दूसरे की पिटाई कर दी। चोटी खींची और पटक-पटककर मारा। वीडियो में दिख रहा है कि दुल्हन के साथ आई एक महिला ने भी प्रेमिका की जमकर पिटाई कर दी। प्रेमिका जब देख लेने की धमकी देकर जा रही थी तो दूल्हे ने भी मारपीट की। मामले में दुल्हन ने थाने पहुंचकर आरोपी प्रेमिका के खिलाफ शिकायत कर दी है।

युवती और दूल्हा एक ही कॉलोनी के रहने वाले

बताया जा रहा कि युवती और दूल्हा नीलेश यादव एक ही कॉलोनी में रहते हैं। नीलेश 2008 में हुए एक मर्डर के मामले में आरोपी रह चुका है। उसने अपने भाई संजय के साथ मिलकर

बेसबॉल बैट से हत्या कर दी थी। मृतक इंदौर के नजदीक गांव में रहता था। पुलिस ने नीलेश के खिलाफ सबूत जुटाकर उसे जेल भेज दिया था। जेल से छूटने के बाद नीलेश यादव वीडियो और फोटो शूटिंग का कामकाज करता है। प्रेमिका और दुल्हन दोनों ने एक-दूसरे को जमकर पीटा। उन्हें एक-दूसरे से हटाने के लिए दूल्हा और उसके परिजन भी पहुंच गए। इनमें से कुछ महिलाओं ने प्रेमिका की पिटाई कर दी। प्रेमिका और दुल्हन दोनों ने एक-दूसरे को जमकर पीटा। उन्हें एक-दूसरे से हटाने के लिए दूल्हा और उसके परिजन भी पहुंच गए। इनमें से कुछ महिलाओं ने प्रेमिका की पिटाई कर दी। दुल्हन-प्रेमिका के बीच विवाद खत्म होने के बाद दूल्हा-दुल्हन के साथ जा रहा था। प्रेमिका ने उसे देख लेने की धमकी दी। इससे गुस्साए दूल्हे ने प्रेमिका की पिटाई कर दी। दुल्हन-प्रेमिका के बीच विवाद खत्म होने के बाद दूल्हा-दुल्हन के साथ जा रहा था। प्रेमिका ने उसे देख लेने की धमकी दी। इससे गुस्साए दूल्हे ने प्रेमिका की पिटाई कर दी।

हंगामा करने वाली युवती ने खुद को प्रेमिका बताया

एसआई विजय धुर्वे ने बताया कि शहर के मल्हारगंज क्षेत्र के दलाल बाग में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह समारोह आयोजित किया गया था। इसमें एक जोड़ा अपने परिवार की रजामंदी से शादी कर रहा था। इसी दौरान गुस्से में एक युवती वहां पहुंची और दुल्हन के साथ मारपीट करते हुए शादी का विरोध करने लगी। युवती के हंगामे के बाद दुल्हन सपना चौहान (निवासी महू) मंडप से उठकर सीधे मल्हारगंज थाने पहुंच गई और लिखित शिकायत दर्ज कराई। दुल्हन का कहना है कि मारपीट करने वाली युवती दूल्हे की प्रेमिका है, जो कि दूल्हे के ही दोस्त की पत्नी है।

इंदौर में दिव्यांग जोड़ों का विवाह, परिजनों ने दुल्हा-दुल्हन को गोद में लेकर दिलाए फेरे

इंदौर। रविवार को कुछ दिव्यांग जोड़ों को उनके परिजनों ने गोद में उठाया और अग्नि वेदी के सात फेरे लगवाए, तो कुछ दिव्यांगों ने शहनाई की मधुर धून के बीच ट्रायसिकल पर बैठकर भी फेरे लिए। रविवार को इंदौर में 31 दिव्यांग जोड़े विवाह सूत्र में बंधे। सामूहिक विवाह में बिहार, राजस्थान के अलावा इंदौर संभाग के जिलों से भी जोड़े आए थे। लक्ष्मीनारायण सेवा संस्थान ने यह विवाह समारोह आयोजित कराया था। समारोह में चार हजार से ज्यादा मेहमानों को भोजन भी कराया गया। संस्था ने विवाह से पहले मेहंदी, महिला संगीत व हल्दी की रस्में भी कराई। बीते 12 सालों में 700 जोड़ों का विवाह संस्था करा चुकी है। रविवार को कुछ दिव्यांग जोड़ों को उनके परिजनों ने गोद में उठाया और अग्नि वेदी के सात फेरे लगवाए, तो कुछ दिव्यांगों ने शहनाई की मधुर धून के बीच ट्रायसिकल पर बैठकर भी फेरे लिए। विवाह के लिए दुल्हनों के मेकअप की व्यवस्था भी संस्था ने कराई थी।

आयोजकों ने बताया कि सर्वधर्म विवाह का उद्देश्य यही है कि गरीब परिवार अपने बच्चों की विवाह कर्ज लिए बगैर कर सकें। जिन बेटियों के माता-पिता नहीं हैं, उनका विवाह भी संपन्न हुआ।

इंदौर में संविधान गौरव यात्रा : युवाओं के साथ कारों की रैली निकालकर दिया संविधान के प्रति जागरूकता का संदेश

इंदौर। संविधान दिवस 26 नवंबर के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री एवं यात्रा के संयोजक बलजीत सिंह चौहान द्वारा शहर में संविधान गौरव यात्रा का आयोजन किया गया। शहर की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए संविधान दिवस के पूर्व में 24 नवंबर को संविधान के प्रति जागरूकता के लिए संविधान गौरव यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा सुबह 10 बजे विजय नगर से रवाना हुई और गीताभवन चौराहे पर बाबा साहब आंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद महू वेटरनरी कॉलेज तक निकाली गई।

यात्रा में बड़ी संख्या में कारें हुई शामिल- यात्रा में सिर्फ कारों को ही शामिल किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में कारें शामिल हुईं, जिसमें युवा सवार थे, यात्रा भारतीय संविधान के प्रति जागरूकता और सम्मान का संदेश देने का प्रयास कर रही थी।विजय नगर मैदान एकत्रीकरण के बाद सभी गीता भवन चौराहे पर स्थित बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचे और वहां माल्यार्पण के साथ यात्रा की विधिवत शुरुआत हुई। इस अवसर पर लाल सिंह आर्य (राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा), गुरु प्रकाश पासवान (राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा), कैलाश विजयवर्गीय (कैबिनेट मंत्री), पुष्यमित्र भार्गव (महापौर) सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

हमारे अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक

कार्यक्रम के संयोजक बलजीत सिंह चौहान भाजपा के प्रदेश मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि यह यात्रा हमारे नागरिकों को यह याद दिलाने का प्रयास है कि हमारे अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ऐसे प्रयासों में अग्रणी रही है, जो समाज को जागरूक और प्रेरित करें।

संविधान हमारी एकता और अखंडता का प्रतीक

उल्लेखनीय है कि 1949 में संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत को एक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। संविधान गौरव यात्रा का उद्देश्य लोगों को संविधान के महत्व के प्रति जागरूक करना और संविधान दिवस के प्रति सम्मान व्यक्त करना है।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री एवं कार्यक्रम संयोजक बलजीत सिंह चौहान ने बताया कि संविधान हमारी एकता और अखंडता का प्रतीक है और हर नागरिक को इसके महत्व को समझना चाहिए। इस यात्रा के माध्यम से भाजपा ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि युवा पीढ़ी को यह समझाने की जरूरत है कि संविधान केवल कानून नहीं, बल्कि समाज को एक दिशा देने वाला दस्तावेज है। संविधान के माध्यम से यह भी बताया जाएगा कि कैसे वे अपने कर्तव्यों का पालन करके देश के विकास में योगदान दे सकते हैं।

संपादकीय

रावत की हार: जीतू को संजीवनी

मध्यप्रदेश में दो विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में से एक विजयपुर पर भाजपा प्रत्याशी व कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत की हार से जहां ग्वालियर चंबल इलाके में अपना वर्चस्व जताने की विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर की कोशिशों को तगड़ा झटका लगा है, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश मल्होत्रा की जीत से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को संजीवनी मिली है। हालांकि केन्द्रीय मंत्री ?व पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान का गढ़ मानी जाने वाली बुधनी सीट पर भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव की फीकी जीत ने क्षेत्र में चौहान की पकड़ पर प्रश्नचिन्ह जरूर लगा दिया है। विजयपुर सीट पूर्व में कांग्रेस के टिकट पर 18 हजार से भी ज्यादा वोटों से जीते रामनिवास रावत द्वारा पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने के कारण खाली हुई थी। रावत कांग्रेस में रहकर भी दुखी थे। रावत कांग्रेस में मूलत~ ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के थे। क्योंकि ग्वालियर चंबल इलाका उनके राजनीतिक रसूख वाला माना जाता है। लेकिन सिंधिया खेमे के होने के बाद भी रावत चार साल पहले सिंधिया द्वारा पार्टी से बगावत के समय उनके साथ नहीं गए थे। यह फांस सिंधिया के मन में कायम रही। यही कारण है कि वो इस बार उन्होंने रावत के चुनाव प्रचार से दूरी बनाए रखी। वैसे भी सिंधिया के भाजपा में आने के बाद से भाजपा में ग्वालियर चंबल इलाके में प्रभाव रखने वाले नरेन्द्रसिंह तोमर शुरू से असहज रहे हैं। क्योंकि सिंधिया के भाजपा में आने से उनका असर कम होने लगा था। यही कारण है कि वो रामनिवास रावत को कांग्रेस से भाजपा में ले आए, जो सिंधिया को कभी पसंद नहीं आया। जबकि तोमर के इस अभियान में मुख?यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सहमति थी। यही कारण है कि रावत के भाजपा में प्रवेश के कुछ समय बाद ही उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया गया और वन मंत्रालय जैसे अहम विभाग भी दिया। रावत की भाजपा में एंट्री और उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाने का खुद भाजपा में भी विरोध हो रहा था। इसके बावजूद रावत ने दबंगई के साथ चुनाव लड़ना चाहा। लेकिन वो नाकाम रहे। क्यों?कि कांग्रेस ने विजयपुर से एक आदिवासी मुकेश मल्होत्रा को टिकट देकर समीकरण बदल दिए। वहां आदिवासी दलित और परंपरागत कांग्रेसियों का गठजोड़ बना। उसे नाराज भाजपाइयों का साथ मिला। परिणामस्वरूप रावत 7 हजार से अधिक वोटो से हार गए। हार के तत्काल बाद उन्होंने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। इस हार के बाद रावत का आरोप था कि आदिवासी वोटों और भीतरघात ने उन्हें हरवाया। लगातार 6 बार विजयपुर से विधायक रहे रावत का राजनीतिक भविष्य संकट में पड़ गया है। उधर भाजपा ने परंपरागत बुधनी सीट जीती जरूर, लेकिन तुलनात्मक रूप से बहुत कम अंतर से। वहां भाजपा के रमाकांत भार्गव को कांग्रेस के राजकुमार पटेल ने कड़ी टक्कर दी। किरार वोट बड़ी संख्या में पटेल के पक्ष में लामबंद हुए। अगर शिवराज आखिरी समय तक मेहनत न करते तो बुधनी भी हाथ से जा सकती थी। उपचुनावों की हार जीत मोहन यादव सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रदेश कांग्रेस जीतू पटवारी को विजयपुर की जीत से नया जीवनदान मिल गया है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद उन्हें प्रदेश का अध?यक्ष बनाया गया था, लेकिन पार्टी में उनकी पूरी तरह से स्वीकार्यता अभी भी नहीं बन पाई है। इसी अनबन के चलते उपचुनाव में प्रचार से बड़े नेता दूर ही रहे। लेकिन पार्टी का आदिवासी चेहरे को टिकट देना सफल दांव रहा और कांग्रेस अपनी यह सीट बचाने में कामयाब रही। इसका श्रेय नि?श्चय ही जीतू पटवारी को मिलेगा और उनकी कुर्सी पर कोई भी प्रश्नचिह्न ?फिलहाल टल गया है। विजयपुर की विजय से कांग्रे?स में फिर जान आने की उम्मीद है।

नजरिया

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

लेखक भारत के राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी रह चुके हैं। संप्रति पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा के डॉ. आंबेडकर चेयर में चेयर प्रोफेसर हैं।

संविधान दिवस : अपने अमृत मूल्यों के साथ जीना होगा

संविधान की उद्देशिका बताती है कि संविधान जनता के लिए है तथा जनता ही अंतिम है, संप्रभु है। यह संविधान का सार है और संविधान का दर्शन भी इसके माध्यम से प्रकट होता है। हम सब जानते हैं कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। हमारे देश का संविधान अब 75 वर्ष हो चुका है। आज़ादी के बाद संविधान-स्वीकृति एक अभूतपूर्व घटना थी। इसकी 75 वीं वर्षगाँठ भारत में उत्सव के रूप में सेलीब्रेट की जा रही है। आज जब भारत के लोग 21वीं सदी में संविधान की ताकत के साथ जी रहे हैं तो वे इस बारे में जागरूक हैं कि यह संविधान हमारे जीवन का रखवाला है, हमारे अधिकारों का संरक्षक है और हमारी गरिमा इससे सुरक्षित रहेगी। हमारा संविधान विकास का पैमाना है। इसमें हमारे देश के हाशिये का समाज भी सुरक्षित है और सुविधा-संपन्न व्यक्ति भी। यह विश्वास ही तो दुनिया के बहुतेरे राष्ट्र अर्जित नहीं कर सके और अनेक बार सैन्य शासन की बलि चढ़ते रहे।

संविधान की इस विश्वसनीयता में भारतीय प्राच्य परम्परा का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे भारतीय लोग केवल संविधान से नहीं जीते। वे जीते हैं अपने आध्यात्मिक शक्ति और नैतिक मूल्यों को भी जो हमारे संविधान में वर्णित मूल्यों को सुरक्षित करने और उसे संवर्धित करने में सहयोगी साबित हुए हैं। यह भारत का सौभाग्य है की हम अपने उन मूल्यों को जोड़कर अपने जीवन-धर्म तय करते हैं। निःसंदेह हमारी लोकतांत्रिक परंपरा में यही मूल्य ही श्रेयष्कर साबित हुए हैं जिससे हम दुनिया के समक्ष गर्व के साथ खड़े होते हैं।

75 वर्ष पूर्व ही इस रचित अगर किसी रचना ने सबसे ज्यादा मानवाधिकारों का संरक्षण किया है तो वह है हमारा भारतीय संविधान। इसलिए आज पूरा भारत राष्ट्र संविधान को सबसे पवित्र ग्रंथ और अपना पथ प्रदर्शक मानता है। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने इसकी प्रारूप समिति में अभूतपूर्व योगदान दिया और उन्होंने जिस मनोभाव से इसे सृजितकर सौंपा था इसे आज उन्हीं का भारत अपने संविधान पर गर्व कर रहा है, सबसे अच्छी बात यही है। आज हमारे देश में सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात हो रही है। आज हमारे भारत में डिगनीटि फॉर इंडियन एंड यूनिटी फॉर इंडिया जैसी बातें हो रही है, इसके पीछे भी संविधान की अपनी शक्ति है। संविधान का अपना स्वाभाविक हस्तक्षेप है। इसे निर्मित करने में अनेक मनीषियों, विदुषियों ने जो अपना योगदान दिया है, वे इस संविधान के दायरे में भारतीय व्यवस्था को चलते हुए जहाँ भी होंगे, प्रसन्न हो रहे होंगे।

जीवन और स्वतंत्रता की मांगें हों, गरिमा व प्रतिष्ठा की मांगें हों, ये मनुष्य के जीवन की बुनियादी मांगें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था एक बार कि हमारा संविधान यह सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है। हमारा संविधान सहस्रों वर्ष की भारत की महान परंपरा, अखंड धारा, उस। धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। हमारे लिए संविधान एक जश्न होना चाहिए, संविधान एक उत्सव होना चाहिए। संविधान के प्रति हमारा आदर-सत्कार पीढ़ियों तक चलते रहना

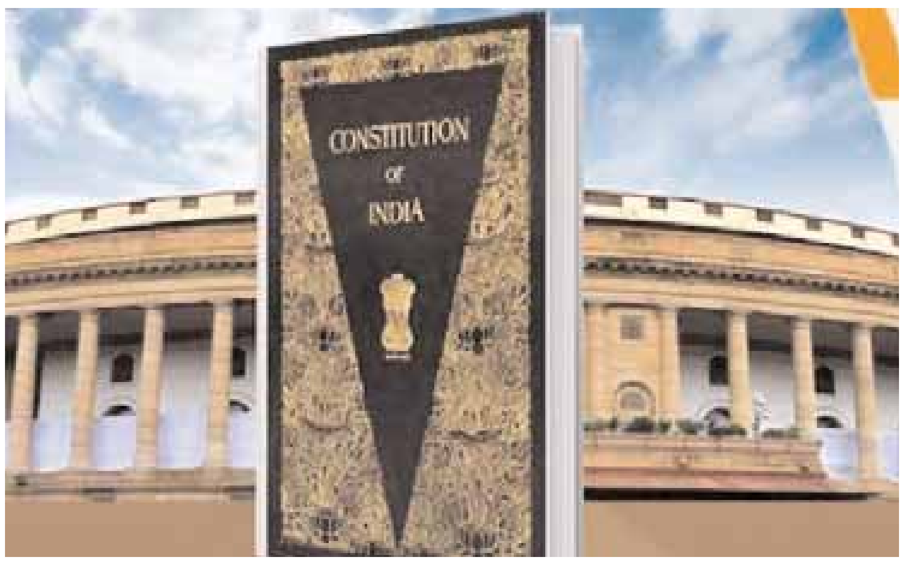

चाहिए। यह संस्कार, विरासत हम लोगों का दायित्व है। इस संविधान दिवस को हमें इसलिए भी मनाना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे है वो संविधान के प्रकाश में है। हर वर्ष संविधान दिवस मना कर हमें अपने आप का मूल्यांकन करना चाहिए। लेकिन अब संविधान को उत्सव के रूप में मनाने के साथ इसके प्रति ज्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। सहज जीवन जीने वाले लोग अभी भी इस पुस्तक के बारे में नहीं जानते। वे पुलिस, कोर्ट, वकील, जज इन्हें ही अपने जीवन का रक्षक मानते हैं। वास्तव में ये लोग भारत के संविधान नहीं हैं। ये इस संविधान के दायरे में भारतीय नागरिकों के हितों के रक्षा हेतु अपने कर्तव्यों के निर्वाहकर्ता हैं।

संविधान में निहित शक्तियों को समझकर आमजन के हितों की रक्षा करना इनका कर्तव्य है। भारत में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद जागरूकता बढ़ी है लेकिन केवल एक आंकड़ा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का ही हम लें कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेकर कितने मामले रजिस्टर किए तो भी हम यह कहने के योग्य नहीं हैं की भारत में सभी लोग सामन गरिमा के साथ जी रहे हैं और उनके हितों का अतिक्रमण नहीं है। विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामले की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है और अभी भी आदिवासी व हाशिये के समाज के लोग अपने अधिकारों को इस संविधान के माध्यम से कैसे सुरक्षित करेंगे, यह उनको पता नहीं है। यह एक चुनौती है। यह एक बड़ी चुनौती है पूरी भारतीय सभ्यता के लिए।

ऐसे में, संविधान के उत्सव के साथ हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के हित-उत्सव के बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। निःसंदेह वर्तमान सरकार द्वारा पीएम आवास योजना, स्टैंडअप इण्डिया योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, स्टार्टअप इण्डिया योजना, डिजिटल इण्डिया योजना, ई-ऑफिस, लाडलीबहना योजना, मुद्रा योजना आदि के माध्यम से भारतीय जनता को सुरक्षित व गरिमामय बनाने का संकल्प दुहराया गया है। सरकार ने स्त्रियों के अधिकारों और उनके सम्मानों को सुरक्षित किया जिसमें बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना बहुत ही महत्त्वपूर्ण योजना रही है। ऐसी अनेक योजनाओं के साथ भारतीय संविधान के आलोक में सरकार ने कल्याणकारी होने के अपने यत्न किये हैं और मन की बात जैसे कार्यक्रम के माध्यम से संविधान के साथ संवाद करने की भी कोशिश की है। इससे हमारे लोकतंत्र को बहुत बल मिला है। आवश्यकता इस बात की है की हमारे न्याय की सुगमता हो और हमारे आमजन में संविधान की भूमिका को ज्यादा ग्रासरूट लेवल पर लाया जाए जिससे लोग जागरूक हों और जागरूक होकर भारत की 75 वर्ष की रोमांचकारी यात्रा को ऐतिहासिक और विशिष्ट बनाएं। इसके लिए निःसंदेह व्यापक स्तर पर जमीनी स्तर पर संविधान उत्सव सतत बनाये रखना आवश्यक होगा जिसकी बात प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्षों पूर्व की थी। इसके साथ संविधान सबका कैसे बने, यह सोच विकसित करना ज़रूरी है।

यदि हमने 'हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये, तथा उसके समस्त नागरिकों कोः सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिये, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिये दृढसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई। यानी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छः विक्रमी को एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसर्पित करते हैं', जैसा व्रत लिया है तो इसमें निष्ठा रखना और अपने कर्तव्य का निर्वाह करना हमारी जिम्मेदारी है।

जागरूक समाज ही सशक्त भारत बना सकता है और 2047 तक भारत को विक्सित राष्ट्र बनाने में मदद कर सकता है इसलिए इस 75वीं वर्षगांठ पर सम्पूर्ण भारत से यह अपेक्षा है की वे अपने अधिकार और कर्तव्यों के बारे में सजग हों जिससे भारत की वैश्विक छवि और अच्छी बन सके। जिन्हें आम नागरिक अपना संविधान और भगवान् मानती है वे अपना एकाधिकार वाली बुद्धि से उन्हें परेशान न करें बल्कि उनकी सहजता को उनका वैशिष्ट्य समझते हुए उन्हें सच में न्याय दिलाएं। हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यह चाहते हैं की भारत का सच में संविधान उत्सव हो तो अपने पद के दुरुपयोग करने वाले लोग कम से कम अपनी सीमाओं में ही संविधान के मूल्यों के साथ भारतीय जनमानस को उनके न्याय दिलाएंगे तो निःसंदेह हमारे देश की सशक्त लीडरशिप को भी मदद मिलेगी और देश भी अपनी गतिशीलता के साथ आगे बढ़ सकेगा। यह संविधान लागू होने का अमृत पर्व है इसलिए भारत को अमृत देश बनाने के लिए अपने अमृत मूल्यों के साथ जीना होगा।

जयंती पर विशेष

डॉ. संजय कुमार

लेखक डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में प्रोफेसर हैं।

डॉ. गौर के स्वप्न में देश संवर्धन के सूत्र

डॉ. हरीसिंह गौर की गणना भारत के उन विभूतियों में की जाती है जिनका राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य योगदान रहा है। उनका इस धरा धाम पर आगमन उस समय हुआ जब भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था।1857 की क्रांति देश में नव चेतना को जागृत कर रही थी और राष्ट्र अपने वीर सपूतों की ओर उसे माता-पिता की तरह देख रहा था जिन्हें भरोसा रहता है अपने लालन-पालन पर कि एक दिन यह अवश्य मेरे संकटों का मोचन बनेगा। एक नया सवेरा होगा , जहां सभी लोग शिक्षित ,सुखी और सद्कर्म को बढ़ाने वाले होंगे। उनके विचार और कर्म दोनों सुराष्ट्र के निर्माण में योगदान देने वाला होगा। ऐसे समय में डॉ.हरीसिंह गौर का जन्म सागर स्थित शनिचरी मध्य प्रदेश 26 नवम्बर 1870 ई में हुआ था। इनके पिता का नाम तख्त सिंह गौर और माता का नाम लाडलीबाई था। इनके पिता कुछ दिनों तक वृटिस गौरमेण्ट में चीफ कास्टेबल के पद पर कार्यरत रहे थे।

डॉ.हरीसिंह को देश की अपेक्षाओं का सदैव ध्यान रहता था। वे सदैव उस भारत के विषय में चिंतन करते थे जहां अशिक्षा और बेरोजगारी अपने चरम पर थी। अहर्निश वे एक समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र का ही चिन्तन करते रहते थे। उनका समृद्धशाली राष्ट्र के सम्बन्ध में मानना था कि बेरोजगारी, स्त्री दुर्दशा और छुआछूत देश की तरक्की सबसे सबसे बड़ा बाधक है। भारत को वे विश्व में अग्रणी पंक्ति पर खड़ा करना चाहते थे। इस सम्बन्ध में वे अंधविश्वास और अशिक्षा को सबसे बड़ा बाधक मानते थे। उन्होंने स्वयं शिक्षा के लिए बहुत संघर्ष और परिश्रम किया था। उन्हें शिक्षा के प्रकाशपुंज का बोध था। शिक्षा ही वह ज्योति है जो तीनों लोकों और तीनों युगों को प्रकाशित करती है। उन्होंने शिक्षा के सम्बन्ध में कहा था कि 'अज्ञानता दासत्व की सहेली होती है' इस लिए शिक्षा सभी मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। डॉ. गौर अपने सपनों के भारत में सर्व सुलभ शिक्षा के पक्षधर थे इस सम्बन्ध में सरकार और देश के सभी लोगों को उत्तरदायी मानते थे। जिसमें सरकार की जिम्मेदारी अधिक होती है।

डॉ. हरीसिंह गौर ने देश और विदेश दोनों जगहों से शिक्षा प्राप्त की थी इसलिए उनकी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण आधुनिक था। इस रूप में समावेशीय शिक्षा उन्हें मानी थी। जहाँ बालक, बालिका और बिकलांग सभी एक साथ विना किसी भेद-भाव की शिक्षा प्राप्त करें। डॉ. गौर कैम्ब्रिज और आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को उच्चाध्ययन की दृष्टि उपयुक्त मानते थे। विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में उनका मानना था की इससे राज्यसत्ता दूर रहे तो अच्छा है। विश्वविद्यालयों पर अनावश्यक सरकारी दबाव ठीक नहीं होता है। अध्ययन-अध्यापन का वातावरण विश्वविद्यालय स्वयं निर्मित करे तो यह श्रेष्ठ परम्परा होगी क्योंकि प्रत्येक विश्वविद्यालय का सांस्कृतिक परिवेश अलग-अलग होता है। विश्वविद्यालय अध्ययन का उत्तम स्थल है। वहाँ से अध्ययन करके विद्यार्थी विश्व में अपने कार्य-कौशल और ज्ञान को प्रमाणित करें। डॉ. गौर ने भारत के दो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय- नागपुर विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति पद के दायित्व का निर्वहन करने के पश्चात अपनी बीस लाख निजी सम्पति से सागर विश्वविद्यालय की स्थापना 19 46 ई. में किया। जिसका मात्र उद्देश्य है की इस बुन्देलखंड अंचल के विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिले। उन्होंने अपने समय में देश के विभिन्न अंचलों सहित विदेशों से भी अच्छे अध्यापकों को यहाँ अध्यापन के लिए आमंत्रित किया था।

यदि डॉ. गौर के सामाजिक कार्यों को देखा जाय तो वे विधिवेत्ता और शिक्षाविद के साथ समाज सुधारक के रूप में भी दिखलायी पड़ते हैं। उनके स्वप्नों के भारत में हर जगह समानता ही समानता थी। वे ऊंच नीच की भावना से दूर सदैव एक सशक्त भारत की कल्पना करते थे। भारत केवल एक भूभाग नहीं है यहाँ की चेतना शाश्वत है उस शाश्वतता में न ही कोइ छोटा है न कोई बड़ा है , सभी सामान हैं। जिसके लिए उन्होंने आजीवन कार्य किया था। महिलाओं की स्थिति में सुधार की दृष्टि से उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। उन्होंने स्त्री को पुरुष के सामान ही अधिकार दिलाने का कार्य किया है। आधी आबादी के सम्बन्ध यह कितना बड़ा कार्य था उसका अनुमान आप लगा सकते हैं। यदि उन्हें अवसर नहीं मिलता तो देश में उनके योगदान कैसे समझा जाता। इसलिए अवसर सबको मिलना चाहिए। अवसर मिलने पर परिणाम अच्छे ही आते हैं। शिक्षा,विज्ञान और प्रशासन में स्त्रियों के योगदान को नजरंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने सिविल मैरीज एक्ट पास कराया जो महिलाओं की सामाजिक बोध की दृष्टि से आवश्यक था। विदेश यात्रा के सम्बन्ध रूढ़ियों को उन्होंने तोड़ा। डॉ. गौर के समय में दक्षिण भारत में देवदासी प्रथा का अत्यधिक प्रचलन था। इसका भी अंत डॉ.गौर के प्रयासों से हो पाया। स्वदेशी उद्योग के संबंध में उनका विशेष उल्लेखनीय कार्य है। उनके प्रयास से अनेक भारतीय उद्योगों को बढावा मिला। उनके ही सद्प्रयास से भारत में डाक टिकट की छपाई प्रारंभ हुई नहीं तो इसकी छपाई यूरोप में होती थी। हिंदू धर्म चैरिटेबल बिल भी उनके द्वारा पास कराया गया था। इस तरह हम देखते हैं कि डॉ. हरीसिंह गौर के द्वारा अनेक सामाजिक कार्यों को किया गया है जिसे स्वस्थ समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण कार्य माना जाना चाहिए।

डॉ. सर हरीसिंह गौर एक शिक्षाविद, विधिवेत्ता के साथ-साथ उच्च श्रेणी के साहित्यकार भी थे। उनके द्वारा भारतीय न्याय विधि के साथ अनेक उपन्यास और कविता संग्रह इत्यादि का भी प्रकाशन किया गया है। यद्यपि वे संविधान से संबंधित अनेक पुस्तकों की रचना किए हैं फिर भी उनके पद्य और उपन्यास का भी साहित्य की दृष्टि से विशेष महत्त्व है। यदि हम उनकी पुस्तकों की बात करें तो 'संपत्ति हस्तांतरण की विधि', 'भारत की दंड विधि संहिता', हिन्दू विधि, रेंडम राइम्स (कविता संग्रह) लैटर्स फ्रॉम हैवेन, हिज ओनली लव (उपन्यास) वेले लेटर्स, हिज लाइफ एंड वर्क्स, द स्पिरिट ऑफ़ बुद्धिस्म आदि अनेक रचनाएं प्रसिद्द हैं। डॉ. हरीसिंह गौर के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के डॉ. वनमाला भवालकर ने 'गौरो हरि' नामक संस्कृत में कविता लिखी है जिसका प्रकाशन संस्कृत पत्रिका सागरिका में हुआ है। डॉ. प्रेम नारायण द्विवेदी द्वारा भी 'जयतु जयतु गौर' संस्कृत में कविता लिखी गई है। डॉ बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा हिंदी माध्यम में 'डॉ. हरीसिंह गौर~ एक प्रेरक व्यक्तित्व' नाम से बहुत अच्छी पुस्तक लिखी गई है। इसी क्रम में हरी सिंह गौर के व्यक्तित्व कृतित्व से प्रभावित होकर डॉ. किरण आर्या के द्वारा 'गौर गौरव गीतिका' का प्रकाशन किया गया है। यह संपूर्ण रचना संस्कृत भाषा के साथ पद्यानुवाद रूप में प्रकाशित है। पद्यानुवादक डॉ. सुकदेव बाजपेयी हैं। इसमें डॉ. सर हरीसिंह गौर के व्यक्तित्व को काव्य भाषा की रूप में उपस्थित किया गया है। सभी पद्यों में कवयित्री के भाव लोक का प्रकाशन हुआ है।

इस प्रकार हम देखते हैं की डॉ.गौर के स्वप्नों के भारत में सबके समान शिक्षा ,समान कार्य और महत्व, समान स्वास्थ्य आदि की कामना की गयी है। ऊँच-नीच के भेद से रहित स्वस्थ समाज की कल्पना उनके स्वाप्नों के भारत में मूल रूप में मिलती है। उनके दृष्टि में शिक्षा,स्वास्थ्य और संस्कृति के संवर्धन से ही देश का संवर्धन सम्भव है।

पालक की पकौड़ी और मीडिया की मस्ती

कटाक्ष

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा 'उरतृप्त'

लेखक व्यंग्यकार हैं।

मीडियाकर्मियों के कैमरों से लैस कमरे के बीच खिचिक-खिचिक की आवाज़ गूँज रही थी। माहौल था एक प्रेस कांफ्रेंस का। तभी एक नेता जी माइकों के झुंड के साथ लगी कुर्सी पर विराजमान हुए। वैसे नेता जी हर संकट में कुशल वक्ता थे, इस बार रेल दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करने की तैयारी कर रहे थे। ठीक उसी समय, उनके पीए ने धीरे से कहा, 'सर, प्रेस कांफ्रेंस होने के बाद आपकी खास पालक पकौड़ी तैयार है।' किसे पता था कि इतनी हल्की सी फुसफुसाहट माइक पर गूंज उठेगी। मीडिया ने इसे सुन लिया और फिर शुरू हुआ एक अजीबोगरीब सवालों का सिलसिला।

पहला मीडियाकर्मी, जो कि 'सवाल उठाने के तरीके' का मास्टर था, बोला, 'आपको पालक पकौड़ी पसंद है? पालक का रंग तो हरा होता है। इसका मतलब क्या आप विशेष पार्टी का समर्थन करते हैं?' नेता जी ने झट से जवाब दिया, 'अरे भैया, मेरे पिता जी हलवाई थे। वे गजब की पालक पकौड़ी बनाते थे। उनका जलवा तो ऐसा था जैसे सारा आकाश छू ले। इसलिए मुझे पालक पकौड़ी पसंद है।'

दूसरा मीडियाकर्मी, जो हमेशा कुछ न कुछ नया उगले बिना चैन से नहीं बैठता, बोला, 'पिता जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आप परिवारवादी राजनीति का समर्थन करते हैं?' नेताजी ने उत्तर दिया, 'क्यों नहीं? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है। तो नेता का बेटा नेता बने, इसमें क्या बुराई है?' जैसे कि उन्होंने कोई तीर चलाया हो।

तीसरा मीडियाकर्मी कूद पड़ा, 'अच्छा, तो आप अभिषेक बच्चन, आलिया भट्ट और अनन्या पांडे जैसों के नेपोटिज़्म का समर्थन करते हैं!' नेताजी ने मुँह बिचकाते हुए कहा, 'अरे भाई, ये तो फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं। बॉलीवुड की बातें क्यों कर रहे हो?'

चौथा मीडियाकर्मी हंसते हुए बोला, 'इसका मतलब आप बॉलीवुड पसंद करते हैं। जबकि आप बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से हैं!' नेताजी ने कहा, 'बस नाम लेने से क्या होता है। डांडिया तो गुजरात से है, लेकिन अब तो यह पूरे भारत में खेला जाता है। तो इसका मतलब क्या मैं गुजराती हो गया?'

पाँचवां मीडियाकर्मी चौंका, 'क्या डांडिया आपकी खास पसंद है? तो क्या आप गुजरात मॉडल के नाम पर अपनी मातृभूमि के खिलाफ जाकर गुजरात का समर्थन करेंगे? क्या आप अडानी और अंबानी के समर्थक हैं?' नेताजी ने हंसते हुए कहा, 'देखो, अगर कोई देश के विकास के लिए काम कर रहा है, तो उनका समर्थन करने में क्या बुराई है?'

छठा मीडियाकर्मी चिढ़ते हुए बोला, 'तो आप अडानी और अंबानी के समर्थक हैं! इसका मतलब तो आप पूंजीवाद का समर्थन करते हैं। फिर तो गरीब आपके लिए कोई मायने नहीं रखते!' नेताजी ने गुस्से में आकर कहा, 'ये भी अजीब बात है। कल मैंने इंडिया-पाकिस्तान का मैच देखा। बाबर आज़म ने कमाल की बल्लेबाजी की। तो क्या अब मैं पाकिस्तानी हो गया?'

सातवां मीडियाकर्मी, जो अपनी बातों से किसी को भी उलझा देता था, बोला, 'तो आपको इतने क्रिकेटरों में केवल बाबर आज़म ही अच्छा लगा। वह भी दुश्मन देश का खिलाड़ी। इसका मतलब आप दुश्मन देश के एजेंट हैं! कहीं आप आतंकवाद के समर्थक तो नहीं हैं?' नेताजी ने चिढ़कर कहा, 'अरे भाई, जब देश में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी हमले हुए थे, तब मैंने ही सबसे पहले दुख व्यक्त करते हुए उस आतंकवादी संगठन की भर्त्सना की थी। तब तुम लोगों को मेरी देशभक्ति का पता नहीं लगा?'

आठवें मीडियाकर्मी ने आखिरी तीर चलाया, 'तो इसका मतलब आपको केवल जैश-ए-मोहम्मद से आपत्ति है। उसे छोड़कर बाकी आतंकवादी संगठन जैसे लश्कर-ए-तोयबा का समर्थन करते हैं? हो न हो, आप आतंकवादी गिरोह में लिप्त लगते हैं। आपकी जाँच होनी चाहिए!' सवालों के बौछार से झल्लाते हुए नेताजी ने कहा, 'हाँ, मैं आतंकवादी हूँ, आतंकवादी!' जैसे ही यह शब्द उनके मुंह से निकले, टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगीः 'फलाने नेता जी का कनेक्शन आतंकवादी संगठन से!'

किसी ने ठीक ही कहा है, 'इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, यहाँ तक कि नेता जी की पालक पकौड़ी भी उन्हें आतंकवादी बना सकती है।' न जाने कब प्रेस कांफ्रेंस ने एक नया मोड़ लिया, जहाँ पकौड़ी की बात करते-करते नेताजी आतंकवाद की चादर ओढ़ बैठे।

सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पी.जी. इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेस प्रा. लि., राउखेड़ी, देवास रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 662, साईं कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक - उमेश त्रिवेदी
संपादक (म.प्र.) - गिरीश उपाध्याय
वरिष्ठ संपादक - अजय बोकिल
स्थानीय संपादक - हेमंत पाल
प्रबंध संपादक - अरुण पटेल

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)

RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,

Mobile No.: 09893032101

Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

विजी श्रीवास्तव

लेखक व्यंग्यकार हैं।

औकात की नाप बढ़ाने के लिए आदिवासी तेल का उलाहना

वे साहब का रूतबा और उनका तेवर दोनों ही बड़े थे। उन्होंने आज वर्मा को नाप दिया। अफसर के कक्ष से निकलकर वो पीड़ा उगलने सीधे मेरे पास आया, तब उसके चैहरे पर ड्रोन उड़ रहे थे। 'हद्द हो गई यार श्रीवास्तओ। मालूम बड़का साहब मुझसे क्या बोले-तुम्हारी औकात मेरे बाल बराबर भी नहीं है' मैंने सोचा बाल तो चलो माइक्रोन्स में ही नाप लो, औकात नापने का कौनसा मेजरमेंट अफसर के पास है। तभी मेरा बुलउआ भी आ गया। मैंने ऐतिहातन टॉयलेट का रूख पहले किया। वहीं पर अपनी शकल आइने में देखी और साहब के बालों की तुलना में अपनी औकात का अंदाज भी लगाया।

चैम्बर में घुसा तो सबसे पहले मेरी नजर उनके सिर पर ही पड़ी। वहां वीरानी छाई हुई थी। किस्मत से मेरा बालोद्यान अभी भी गुलजार था। लेकिन बात कैश राशि और केश राशि थी। कैश राशि वे सम्पन्न थे, मेरा हेअर स्टेटस उनसे खासा अच्छा था। सौभाग्य से हमारी चर्चा फाइलों तक ही सीमित रही और मैं कैश लेस ट्रांजिक्शन के साथ अपनी माइक्रो औकात सुरक्षित लिए, वापस लौट आया। हमारे बाद अंदर जाने की बारी उच्च श्रेणी बाबू रामाधार की थी। वह खुद को उच्च नहीं, सर्वोच्च समझता था। रामाधार को निराधार ही दूसरों के फटों में टांग डालने की आदत थी। वर्मा अभी भी मेरे पास बैठा हुआ था। उसके चैहरे पर बारह बज रहे थे। दुनियां के सभी ऑफिसों में ग्यारह बजकर उन्सठ मिनिट तक बजाए गए लोग, बारह बजे वाले का भरपूर मजा लेते हैं। रामाधार भी अंदर जाने से पहले वही सुख भोग करने हमारे पास आया था।

मैंने गौर किया। उसके हाथ में एक तेल की शीशी थी। सबको पता था कि रामाधार के पास अफसरों को लगाने के लिए बातों की चाशनी, मक्खन, क्रीम और जाने क्या क्या होता है। लेकिन आज तो निखालिस तेल ही था। मैंने पाया कि वह कोई आदिवासी तेल था। वर्मा के जले पर नमक छिड़क कर वो अंदर चला गया तो मैंने अपने कम्प्यूटर पर गूगल खोलकर उस तेल के बारे में रिसर्च शुरू कर दी। आदिवासी तेल के नाम से सोशल साइट्स पर कितने ही लोक-लुभावन विज्ञापन थे। इनमें निर्माता, निर्देशक, मार्केटिंग हैड्स और यहां तक कि मॉडल भी आदिवासी युवा ही थे।

ग्रामीण विभागों से जुड़े हर सरकारी और गैर सरकारी मानुष को वनवासियों का तेल निकालने का इतिहास पता होता है। लेकिन अब वो वाला समय, यू टर्न ही नहीं अबाउट टर्न ले चुका है। अब तक जिनका तेल निकाला जाता रहा, वे ही तेल निकालना सीख गए हैं। खट्टे मीठे, तोरे अनुभवों ने उनकी नई पर्सनॉलिटी डेवेलपमेंट का काम किया है। शहर के लोगों को विश्वास था कि वे गांव के लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। आज, ग्रामीण देवता आश्वस्त हैं कि वे शहरी लोगों को जी भरकर बेवकूफ बना सकते हैं।

मोबाइल के आगोश में समाई नई टेक्नोलॉजी ने भी उन्हें धूल में फूल खिलाने के बजाय, धूल में लट्ठ लगाने का हुनर तेजी से सिखाया। सदियां गुजरे, छोटा अ से अनार, बड़ा आ से आम, छोटी इ से इमली पर अटकी उनकी गाड़ी को बड़ी ई से ई-लर्निंग इतनी भा गई है कि वे आपको छोटा उ से आप जो भी बन सकें, बना सकते हैं। सोशल मीडिया से जुड़कर वनवासी विकास को नई दिशाएं मिली हैं। बहुत बड़ी संख्या में बिना प्लेटफार्म टिकिट के, इन प्लेटफार्मों पर फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक प्रोडक्टस लेकर वे उतर पड़े हैं। तेल और शैम्पू ही नहीं, बड़ी सी बड़ी बीमारियों का इलाज इनकी मुट्ठी में है। शिलाजीत की फैक्ट्री इनके पास वाले नाले में है। कचरे जैसी दिखती वनस्पति से यह महीने- दो महीने में कैंसर को दूर कर सकते हैं। गौद भरना हो तो चार महीने काली गोली खाने भर से दशमलव भर का एम्ब्रियो, फुटबाल में तब्दील हो सकता है। मुंहासे, बवासीर, भगंदर, नामर्दगी जैसी बीमारियों के पुश्तैनी इलाज वे ग्यारंटी से करने का दावा करते हैं। ये अपने तेल की मॉडलिंग करते हुए अपनी लंबाई से सवा गुना बड़े बाल खोल कर दिखाते हैं। इससे बाल विहीन हो चुके और होने जा रहे लोगों में लंबी-काली, घनी आशाओं का संचार होता है। बाल बढ़ाने को आतुर भारतीय नर-नारियों को अब नारियल, शीकाकाई, भृंगराज और अरीठा के प्रति विश्वास नहीं रहा। इसलिए भी वे सोशल मीडिया पर आदिवासी तेलों को ललचाई नजरों से देखकर, भरोसे के साथ फॉरेस्ट फैक्ट्रियों में निर्मित तेल और शैम्पू शिरोधार्य कर लेते हैं।

बाल-कब बवाल मचा दें, कह भी तो नहीं सकते। सौभाग्य से अभी तक सुरक्षित जीवन इसलिए जी रहा हूं कि मेरे कपड़ों पर कभी असंवैधानिक बाल नहीं मिले। समय खराब चल रहा हो तो किसी सुकेशी का बाल कहीं से भी आकर चिपक सकता है। कपड़ों पर आरूढ़ एक बाल की भी खाल निकालकर डीएनए करने वाली फॉरेन्सिक विशेषज्ञ घर में ही पाई जाती हैं। वे झट्ट से बता देती है कि पाया गया बाल पड़ोस वाली चुड़ैल का है या दफ्तर वाली भूतनी का। इस मुकदमे में सफाई पक्ष के सारे तर्क माननीय अदालत द्वारा सिरे से खारिज कर दिए जाते हैं। कपड़ों पर बाल चिपकने का कारण भले ही कितनी भी प्राकृतिक घटना हो किन्तु परिणाम जघन्य अप्राकृतिक कृत्य के रूप में सामने आने की पूरी संभावना पैदा कर सकते हैं। इसलिए सजग भारतीय नागरिक, मौबाइल से चैट और कपड़ों से बाल झाड़कर ही घर में सज्जनतापूर्वक प्रवेश करता है। मैं भी सज्जानतापूर्वक घर पहुंचा तो वहां डाईनिंग टेबल पर वनांचल से आई एक तेल की शीशी विराजी थीं। मेरे मुंह से निकला-हाय आप कब आईं। तेल की शीशी ने जवाब दिया-आपकी श्रीमती ने ही बाइज्जत बुलवाया है। पर मिस्टर श्रीवास्तव ज्यादा आंखें मत फैलाओ। तुम्हारे उड़ते हुए बालों को तो हम देख लेंगे लेकिन अपनी औकात का ध्यान आप खुद रखो, कहीं किसी के बाल के नाप से छोटी न हो जाए।

संविधान दिवस पर विशेष

भूपेन्द्रसिंह परिहार

लेखक अधिवक्ता हैं।

भारत में नागरिक कर्तव्य बोध

भारत में संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य, राष्ट्र के नागरिकों को संविधान के बारे में जागरूक करना और संविधान के महत्व को समझाना है। साथ ही, संविधान के आदर्शों और अवधारणाओं का विस्तार भी इसका उद्देश्य है। वहीं, नागरिक कर्तव्य, नागरिकों को जिम्मेदार नागरिकता की ओर ले जाते हैं और राष्ट्र की प्रगति में योगदान करते हैं। किसी लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए संविधान देश के नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को तय करता है। हर साल भारतीय संविधान के बारे में नागरिकों को जागरूक करने और संविधान के महत्व व संविधान निर्माताओं के विचारों और अवधारणाओं को प्रसारित करने के उद्देश्य से संविधान दिवस मनाया जाता है। साथ ही राष्ट्र के नागरिकों में नागरिकता बोध बढ़े यह महत्वपूर्ण है। नागरिक ना सिर्फ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे बल्कि पहले नागरिक कर्तव्यों का सत्यनिष्ठा से पालन करें।

भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल 26 नवंबर को हमारे देश में 'संविधान दिवस' के रूप में भी जाना जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ।

इसे आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को भारत सरकार द्वारा नागरिकों के बीच संविधान मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर साल नवंबर के 26वें दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने के निर्णय को अधिसूचित किया। इसके तहत भारत के नागरिक कर्तव्य पालन अभियान की शुरुआत की गई। वहीं केंद्र व राज्य सरकारों के शिक्षा मंत्रालय का स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग छात्रों में संविधान मूल्यों की भावना को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों में विभिन्न गतिविधियों का संचालन करते हैं।

भारत के संविधान में शुरुआत में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। साल 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसके बाद, साल 2002 में 86वें संविधान संशोधन के ज़रिए एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग IV-A अनुच्छेद 51-क में शामिल किया गया था।

भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं।

संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं,

राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना,

स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोकर रखना और उनका पालन करना,

भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करना तथा आह्वान किये जाने पर राष्ट्रीय सेवा करना,

भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या सांप्रदायिक विविधताओं से ऊपर उठकर सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना तथा महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना,

देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना ,

वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना,

वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना विकसित करना ,

सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा का परित्याग करना,

व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके, और छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना (86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया)।

इन सभी संवैधानिक कर्तव्यों का नागरिकों के द्वारा पालन करने पर कोई भी राष्ट्र खुशहाल व प्रगतिशील बन सकता है लेकिन प्रश्न है कि क्या संविधान दिवस पर हम ईमानदारी से इस विषय पर विचार व चिंतन कर रहे है कि हम राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन करते हैं ? यह पृथ्वी हमें कितना कुछ देती है लेकिन बदले हम उसे प्रदूषण व गंदगी के अलावा क्या दे रहे हैं। आधुनिक जीवनशैली ने हमें वर्तमान व भविष्य के प्रति विचार करने से विमुख कर दिया है। भारत के संविधान में दिये मौलिक अधिकारों के प्रति आज हर भारतीय नागरिक हायतौबा मचाता रहता है लेकिन क्या हम मौलिक कर्तव्यों के पालन के लिए तत्पर रहते है ?

अब जब दिनोंदिन संविधान में दिये मौलिक कर्तव्यों का महत्व बढ़ रहा है और राष्ट्र, समाज व हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए नागरिक कर्तव्यों के पालन पर बल दिया जा रहा है ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष में 'पंच परिवर्तन' अभियान के साथ समाज कल्याण व जागरूकता के लिए समाज के बीच कार्य कर रहा है। पंच परिवर्तन में मुख्य रूप से सामाजिक समरसताः समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सौहार्द और प्रेम बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना।

कुटुम्ब प्रबोधनः परिवार को राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली इकाई के रूप में संवर्धित करना।

पर्यावरण संरक्षण : पृथ्वी को माता मानकर पर्यावरण संरक्षण हेतु जीवनशैली में बदलाव।

स्वदेशी और आत्मनिर्भरताः देश की स्वदेशी अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता पर जोर।

नागरिक कर्तव्यः प्रत्येक नागरिक का सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन और राष्ट्रहित में योगदान।

अक्सर भारतीय नागरिकों पर आरोप लगता है कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह रहते हैं। हमें नागरिक बोध नहीं रहता। इस बार संविधान दिवस पर हम सब भारत के नागरिक उक्त बातों का विशेष ध्यान रखें व संविधान दिवस को सच्चे अर्थों में आत्मसात करें। नागरिक बोध का विशेष ध्यान रखें। भारत का नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों की चिंता से पहले कर्तव्यों पर ध्यान दे, तब हमारे संविधान निर्माताओं का लक्ष्य व समर्पण पूर्ण होगा। वहीं भारत का संविधान सही अर्थों में सभी के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा।

संविधान दिवस पर विशेष

नृपेन्द्र अभिषेक नृप

लेखक स्तंभकार हैं।

संविधान पर बहस : अधिकार, सुधार और चुनौतियां

भारत का संविधान देश की आत्मा और लोकतंत्र की नींव है, जो नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का संरक्षक है। यह हमारी विविधता में एकता, धर्मनिरपेक्षता, और समानता को सुनिश्चित करता है। संविधान न केवल कानून का स्रोत है, बल्कि राष्ट्र की सामूहिक आकांक्षाओं का प्रतिबिंब भी है। भारत का संविधान, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार स्तंभ है, जिसे 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि हमारे मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता को याद किया जा सके। संविधान के तहत सरकार की शक्ति और उसके दायित्वों की सीमा निर्धारित की जाती है, और यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी संस्था, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर सके।

हाल के वर्षों में 'संविधान ख़तरे में है' की आवाज़ विपक्षी दलों द्वारा बार-बार उठाई गई है। वहीं केंद्र सरकार इन दावों को खारिज करते हुए कहती है कि वह संविधान की रक्षा और समृद्धि के लिए काम कर रही है। आइए, संविधान दिवस के इस अवसर पर सरकार और विपक्ष की दलीलों का मूल्यांकन करें और केंद्र सरकार की कुछ विवादास्पद कार्रवाइयों की चर्चा करें, जिन पर विपक्ष का आरोप है कि वे संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध हैं।

विपक्ष के आरोपः 'संविधान ख़तरे में है'

विपक्षी दलों का मानना है कि मौजूदा सरकार संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को बाधित कर रही है, जिससे लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो रही हैं। विपक्ष के अनुसार, कुछ प्रमुख मुद्दे जिनके आधार पर वे यह दावा करते हैं। जैसे कि पहला मुद्दा , संवैधानिक संस्थाओं पर सरकार के नियंत्रण का आरोप है। विपक्ष का आरोप है कि मौजूदा केंद्र सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं जैसे कि न्यायपालिका, चुनाव आयोग, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) पर दबाव बढ़ाया है। उनका मानना है कि इन संस्थाओं की स्वतंत्रता सरकार द्वारा बाधित की जा रही है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। विपक्षी नेताओं का दावा है कि न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार का बढ़ता दखल, निर्णयों पर दबाव, और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

दूसरा मुद्दा मौलिक अधिकारों की अवहेलना का है।विपक्ष का यह भी कहना है कि मौजूदा सरकार ने मौलिक अधिकारों की अवहेलना की है। आलोचना की जाती है कि सरकार ने विरोध प्रदर्शन और असंतोष की आवाज़ों को दबाने के लिए कड़े कानूनों का इस्तेमाल किया है, जैसे कि राजद्रोह कानून, UAPA (गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम), और सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA)। इसके अलावा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदियों और स्वतंत्र मीडिया के ऊपर दबाव बढ़ाने का भी आरोप लगाया जाता है।

जबकि तीसरा मुद्दा संविधान संशोधन का दुरुपयोग का है। विपक्ष यह भी कहता है कि सरकार ने संवैधानिक संशोधनों का दुरुपयोग कर कुछ कानूनों को लागू किया है, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाते हैं। वे कहते हैं कि कुछ प्रमुख विधायी निर्णय, जैसे कि जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करना और नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) संविधान की संघीय ढांचे और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। चौथा मुद्दा, धर्मनिरपेक्षता और समानता पर खतरा का है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार की नीतियाँ देश की धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक समानता को कमजोर कर रही हैं। उदाहरण के लिए, CAA को लेकर उनके विचार हैं कि यह एक खास धार्मिक समुदाय के खिलाफ भेदभावपूर्ण है। वे यह भी आरोप लगाते हैं कि अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ा है, जो संविधान के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के खिलाफ है।

केंद्र सरकार की दलीलें: 'संविधान की रक्षा और सुधार'

विपक्ष के आरोपों का सामना करते हुए, केंद्र सरकार संविधान की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की बात करती है। सरकार का मानना है कि उसके कई निर्णय संविधान के मूल्यों को सुरक्षित रखने और राष्ट्रहित में सुधार लाने के लिए हैं। केंद्र सरकार इन मुद्दों को काउंटर करते हुए कुछ तर्क देता रहा है। जैसे कि पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता की सुरक्षा मुद्दा है।सरकार का मानना है कि यू ये पी ए (UAPA) जैसे कड़े कानूनों का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। उनका कहना है कि किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा उसके नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ी होती है, और इसके लिए कड़े कानूनों की आवश्यकता है। सरकार का यह भी दावा है कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करना राष्ट्रीय एकता और अखंडता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

सरकार का दूसरा तर्क है विकास और सुधार के लिए संविधान में बदलाव करने का। सरकार का तर्क है कि संविधान में बदलाव करने का अधिकार संसद के पास है, और यह बदलाव राष्ट्रीय हित और विकास के लिए किए गए हैं। उदाहरण के लिए, सरकार का कहना है कि CAA का उद्देश्य धर्म के आधार पर उत्पीड़ित लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है, न कि किसी विशेष समुदाय के खिलाफ भेदभाव करना। उनका मानना है कि संवैधानिक बदलावों से ही विकास के नए द्वार खुलते हैं।

तीसरा तर्क, संविधान की आत्मा का सम्मान का है। केंद्र सरकार का कहना है कि वह संविधान की आत्मा का सम्मान करते हुए काम कर रही है। प्रधानमंत्री और अन्य प्रमुख नेताओं का कहना है कि सरकार का हर कदम संविधान की धारा और भावना के अनुरूप है, और उन्होंने विकास, समानता, और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। जबकि चौथा तर्क संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता का संरक्षण का देता है। सरकार का दावा है कि उसने संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को बनाए रखा है और न्यायपालिका, चुनाव आयोग, और अन्य संस्थाओं की निष्पक्षता को सुदृढ़ किया है। उनके अनुसार, न्यायपालिका में सुधार, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जो कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक हैं।

कुछ विवादास्पद कदम और उनके संवैधानिक पहलू

विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों की पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार के कुछ निर्णयों की संवैधानिक समीक्षा करना आवश्यक है। जिसमें पहला है, जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करना। अगस्त 2019 में, केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाने का निर्णय लिया, जिससे जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति समाप्त हो गई। इस कदम को संविधान संशोधन के रूप में देखा गया, और इस पर संवैधानिक सवाल उठे। कई कानूनी विशेषज्ञों और विपक्षी दलों का मानना है कि यह कदम संघीय ढांचे और राज्य की स्वायत्तता के विरुद्ध था। वहीं, सरकार का कहना है कि यह निर्णय राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के लिए आवश्यक था। दूसरा, नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का मुद्दा, इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। इस कानून पर व्यापक विरोध हुए और इसे संविधान की धर्मनिरपेक्षता और समानता के सिद्धांत के विरुद्ध बताया गया। सरकार का दावा है कि यह कानून उन लोगों की सुरक्षा के लिए है, जिन्हें उनके देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। तीसरा, कृषि कानून और उनका निरसन करना। 2020 में केंद्र सरकार ने तीन कृषि कानून पारित किए, जो कि किसान समुदाय के बीच विवादास्पद बने रहे। इन कानूनों को बिना पर्याप्त चर्चा के पास किए जाने को लेकर संवैधानिक सवाल उठे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह संविधान की संघीय भावना का उल्लंघन था, क्योंकि कृषि राज्य का विषय है। बड़े पैमाने पर विरोध और आंदोलन के बाद, सरकार ने अंततः इन कानूनों को निरस्त कर दिया।

इसके अतिरिक्त चौथा, मीडिया पर नियंत्रण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा है। केंद्र सरकार पर मीडिया को नियंत्रित करने और पत्रकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का आरोप भी लगा है। कई पत्रकार और मीडिया संगठन मानते हैं कि आलोचनात्मक रिपोर्टिंग के कारण उन्हें कानूनी मामलों का सामना करना पड़ता है। विपक्ष इसे संविधान में वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन मानता है, जबकि सरकार का कहना है कि फेकझ्र न्यूज़ और राष्ट्र विरोधी प्रचार को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं।

संविधान दिवस के अवसर पर, यह चर्चा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है कि हमारे संविधान की सुरक्षा और संवर्धन में सरकार और विपक्ष की भूमिका कैसी होनी चाहिए। संविधान की आत्मा को बनाए रखना और उसमें सुधार करना दोनों ही आवश्यक हैं। परंतु सुधार का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना की जाए। सरकार और विपक्ष दोनों को चाहिए कि वे संविधान को एक पवित्र दस्तावेज के रूप में सम्मानित करें, जो हमारे लोकतंत्र की नींव है।संविधान के प्रति जागरूकता और उसकी सुरक्षा के लिए सभी नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए। चाहे जो भी दल सत्ता में हो, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान, और समानता की स्थापना हर सरकार की जिम्मेदारी है।

संविधान दिवस विशेष

डॉ. चित्रा माली

लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।

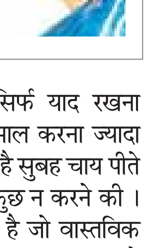

संविधान में हम भारत के लोग

संविधान में लिखे शब्दों को सिर्फ याद रखना जरूरी नहीं बल्कि उनका इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है और हमें आदत हो गई है सुबह चाय पीते हुए ऐसी खबरें पढ़ने की और पढ़कर कुछ न करने की । यह संवाद फिल्म '200 हल्ला हो' का है जो वास्तविक घटना पर आधारित है । 2004 में नागपुर (महाराष्ट्र) में दलित महिलाओं ने एक स्थानीय गुंडे,बलात्कारी को भरी अदालत में मौत के घाट उतार दिया था । इस घटना के बाद महिला आयोग के द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाता है। जिसके अध्यक्ष रिटायर्ड जज विट्ठल डांगले (अमोल पालेकर) को बनाया जाता है जो स्वयं दलित है लेकिन जज होने से उनकी सामाजिक हैसियत सामान्य दलितों पिछड़ों से भिन्न है । वे संविधान को सर्वोपरि मानते हैं उनका मानना है कि न्याय के सामने जाति-धर्म का हवाला देना बेकार है । इस पर नायिका आशा सुर्वे (रिंकु राजगुरु) कहती हैं कि 'जाति के बारे में क्यों न बोलूं सर,जब हर पल हमें हमारी औकात याद दिलाई जाती है' । ये फिल्म दलित पिछड़ों के साथ होने वाले जघन्य अपराधों पर पसरी खामोशी पर कई कड़े सवाल उठाती है और उनके जवाब तलाशती भी है। इसके पूर्व भी कई फिल्मों में दलित और पिछड़ी जातियों के साथ हो रहे अन्याय को दिखाया गया है और उन पर विमर्श भी हुआ है । कुछ वास्तविक घटनाओं का चित्रण भी कई फिल्मों में किया गया है लेकिन हमारी संवेदनाओं का लगातार ह्रास होने से हम इस दर्द को,अन्याय को न देख पा रहे हैं और न ही महसूस कर पा रहे हैं । बहरहाल 26 नवंबर को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संविधान की प्रस्तावना का पाठ सभी लोगों के द्वारा किया जायेगा,इसमें वे लोग भी शामिल होंगे जिनकी आस्था भारतीय संविधान में नहीं हैं और वे अपने अनुसार संस्थाओं को संचालित करते हैं । एक तबका उन लोगों का भी है जो संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए मुहिम चला रहे हैं । जब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं या उसका पाठ करते हैं तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माताओं ने इसका निर्माण भारत की विविधता से भरी संस्कृति को ध्यान में रखकर किया था जिसमें कास्ट,क्लास और जेंडर के विभेद को भी प्रतिबद्धता के साथ समाप्त करने की कोशिश की गई है लेकिन इतने वर्षों बाद भी कास्ट,क्लास,जेंडर और वर्ग के भेदभाव को हर जगह देखा जा सकता है । जाति के आधार पर लोगों को प्रताड़ित करने की खबरें हर रोज न्यूज़ चैनल और अखबारों में पढ़ व देख सकते हैं । न्याय व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद भी इन घटनाओं को रोका नहीं जा सका है । इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता हैं कि आज भी जाति की जड़ें कितनी मजबूत हैं । जेंडर और कास्ट के आधार पर कई वीभत्स घटनाएं घटित हुई हैं जो आज भी लोगों के जेहन में ताजा है । जेंडर,जाति के बाद वर्ग के आधार पर भी कई घटनाएं रोज घटित होती है जिनकी एफ.आई. आर. तक दर्ज नहीं हो पाती हैं क्योंकि वे रसूखदार तबके के लोग हैं । बावजूद इसके भी संविधान का महत्व बरकरार है उन लोगों के लिए जो भारतीय संविधान में आस्था रखते हैं और न्याय के लिए प्रतिबद्ध है जो एक उम्मीद भी है कि संविधान के अतिरिक्त अन्य कोई और व्यवस्था मान्य नहीं है । संविधान का निर्माण अन्तिम जन के हितों की रक्षा के लिए किया गया था लेकिन संविधान को लागू करने वालों की मंशा या कहें प्रतिबद्धता में कमी के चलते उस महान लक्ष्य को आज भी प्राप्त नहीं किया जा सका है जो भारतीय संविधान के नीति निर्माताओं ने भारत देश के लिए तैयार किया था । भारतीय संविधान की वर्तमान प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न, समाजवादी,सेकुलर, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्प व्यक्त किया गया है । 1976 में बयालीसवें संविधान संशोधन के बाद समाजवाद और सेकुलर शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है । भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना इस प्रकार थी 'हम भारत के लोग,भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न,लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक,आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार,अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।' हम भारत के लोग....इस संविधान को अंगीकृत,अधिनियमित और आत्मार्पित करते है । तीन जनवरी 1977 में प्रभुत्व संपन्न गणराज्य के स्थान पर 'समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य' शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक एक शब्द का अपना विशिष्ट अर्थ और महत्वपूर्ण स्थान है जो भारत को एक लोकतंत्रात्मक राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं । भारतीय संविधान हर एक नागरिक की स्वतंत्रता और स्वतंत्र विकास के लिए वचनबद्ध है । भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है जिससे किसी भी नागरिक को उसके चाहने पर भी नहीं वंचित नहीं किया जा सकता है। यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का समावेश भी इसमें किया गया है ताकि कल्याणकारी राज्य का सपना साकार किया जा सके । इसी के साथ नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन भी भारतीय संविधान में किया गया है। आर्टिकल 14 में भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है का प्रावधान किया गया है । आर्टिकल 15 व 16 में वर्णित है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म,मूलवंश, जाति,लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है जिसमें वाक स्वतंत्रता, समवेत होने,संघ बनाने,संचरण, निवास और वृत्ति की स्वतंत्रता का समावेश किया गया है। आर्टिकल 20 में विधि के अधीन दोषसिद्धि के बाबत सुरक्षा का अधिकार, दोहरे दंड और स्वयं को अपराध में फसाने के विरुद्ध संरक्षण का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 21 जिसमें संविधान की आत्मा गूंजती है जो किसी भी व्यक्ति को मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार प्रदान करता है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत आर्टिकल 21क में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया जो राज्य की जिम्मेदारी है । आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यवहार का प्रतिषेध व आर्टिकल 24 परिसंकटमय नियोजन में बालकों को लगाने का प्रतिषेध करता है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है । धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25, किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति में करों के संदाय में स्वतंत्रता आर्टिकल 27, राज्य की शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में सम्मिलित होने की स्वतंत्रता आर्टिकल 28, इसके अतिरिक्त शिक्षा व संस्कृति के अधिकार भी मौलिक अधिकारों में शामिल हैं जिन्हें भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है । राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को परिभाषित किया गया है जिससे राज्यों का चरित्र कल्याणकारी हो और वे बिना किसी भेदभाव के महिलाओं, बच्चों, कमजोर व दुर्बल तबकों के लिए उनके विकास के लिए कल्याणकारी योजनाओं का निष्पादन करें। इसके साथ साथ सभी नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं जिनका पालन किया जाना अनिवार्य है जो संविधान के प्रति हमारी आस्था और प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हैं लेकिन वर्तमान में घटित घटनाएं कहीं न कहीं कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को भी ध्वस्त करती हैं और साथ ही व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के हनन को भी उजागर करती है। आर्टिकल 51क में उल्लेखित कर्तव्यों का भी मखौल कई चर्चित लोगों के द्वारा उड़ाया गया है जो निंदनीय है । आर्टिकल 15 फिल्म उन्नाव की घटना पर बनाई गई है जो भारतीय संविधान की शपथ लेने वालों को भी सवालों के कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करती है । भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया को जानने समझने के लिए श्याम बेनेगल द्वारा बनाए गए संविधान धारावाहिक को देखा जाना चाहिए। गहन विचार विमर्श की एक लंबी अवधि 2 वर्ष 11 माह 7 दिनों के बाद इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का निर्माण किया गया जो भारत के स्वरूप और अस्तित्व को प्रकट करता है ।

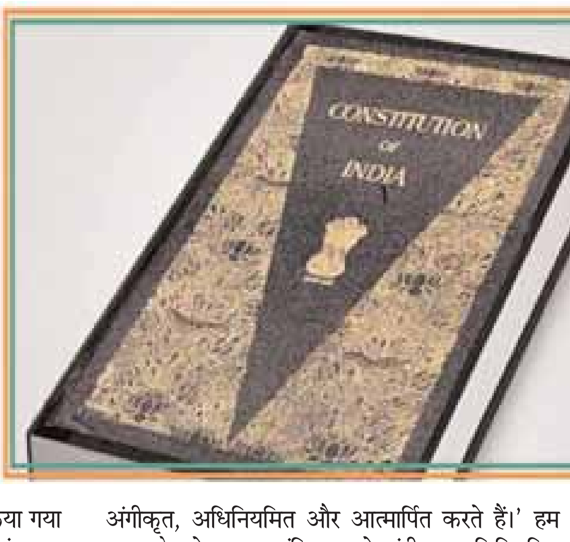

इस संविधान दिवस पर यह आवश्यक हो जाता है कि हम भारत के लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सिर्फ पाठ न करें,बल्कि उसे याद रखते हुए व्यवहारिक जीवन में कार्यान्वित भी करें । साथ ही देश में हो रही घटनाओं पर विचार विमर्श के साथ सक्रिय प्रयास भी करें उन्हें रोकने का जिससे संविधान की मूल आत्मा को बचाया जा सके ।

सीएमओ ने बस स्टैंड का किया निरीक्षण, व्यवस्था सुधारने दिये निर्देश

बैतूल। बस स्टैंड पर व्यवस्थाओं को लेकर मिल रही शिकायत पर कलेक्टर बैतूल नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने त्वरित संज्ञान लेकर मुख्य नगरपालिका अधिकारी बैतूल को व्यवस्थाएं सुधारने की निर्देश दिए हैं। सीएमओ सतीश मात्सानिया ने कोठी बाजार स्थित बस स्टैंड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर पेयजल और रोशनी की समस्या पाए जाने पर सीएमओ ने पेयजल की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने और बंद पड़ी लाइटों को सुधारकर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश अधीनस्थ अमले को दिए। मौके पर गंदगी पाई जाने पर भी सीएमओ ने बस स्टैंड पर प्रभावी ढंग से नियमित साफ सफाई किए जाने के लिए निर्देशित किया। सीएमओ सतीश मटसेनिया ने बताया कि निरीक्षण के दौरान बस स्टैंड पर कई बस मालिकों द्वारा कंडम बसों को स्थाई रूप से खड़ा रखा जाता है। जिससे नगर पालिका को साफ सफाई और रखरखाव में समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके लिए परिवहन एवं यातायात पुलिस के माध्यम से नियमानुसार उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये है। बस स्टैंड पर महिला प्रतीक्षालय में प्रकाश की उचित व्यवस्था न होने पर बिजली विभाग के माध्यम से रोशनी की व्यवस्था बनाने को कहा है।

अधिवक्ता दीपक पाल बने राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के जिला सह प्रभारी

बैतूल। राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संगठन ने अधिवक्ता दीपक पाल को बैतूल जिला सह प्रभारी के पद पर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश चंद्र द्विवेदी और राष्ट्रीय महामंत्री नवीन चंद्र शुक्ला द्वारा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष (संत प्रकोष्ठ) परम पूज्य संत श्री विष्णु जी, प्रदेश अध्यक्ष राकेश तिवारी, प्रदेश महामंत्री प्रीतम सिंह चौहान और बैतूल जिला अध्यक्ष जगदीश राठौर की अनुशंसा पर की गई। नियुक्ति के बाद संगठन के सभी कार्यकर्ताओं ने दीपक पाल को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान दीपक पाल ने संगठन के राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला स्तर के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे संगठन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण से कार्य करेंगे।

खड़े ट्रक को दूसरे ट्रक ने मारी टक्कर, दोनों ट्रक क्षतिग्रस्त

टक्कर से 20 फीट दूर खेत में जाकर पलटा ट्रक

बैतूल। सोमवार सुबह भोपाल-नागपुर नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। मुलताई के ग्राम चैनपुर के पास दो ट्रकों में टक्कर हो गई। जिससे दोनों ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। एक ट्रक नेशनल हाईवे से लगभग 20 फीट दूर खेत में जाकर पलट गया है। बताया जा रहा है कि कन्हान महाराष्ट्र से नीमच क्वाइल लेकर ट्रक क्रमांक एमएच-40/बीजी-8847 जा रहा था। चैनपुर के पास ट्रक चालक श्याम सिंह निवासी बगोड़ा ने ट्रक खड़ा किया और कुछ देर के लिए आराम करना चाहा। वह ट्रक से उतरकर पुलिया पर बैठे ही थे कि पीछे से आए ट्रक क्रमांक आरजे-50/जीबी-0056 ने खड़े ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से ट्रक 20 फीट दूर खेत में गहराई में जा गिरा। जिस ट्रक ने टक्कर मारी, उसमें बिनोला भरा हुआ था। टक्कर के टक्कर मारने वाले ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। इधर श्याम सिंह ने बताया कि वह अगर ट्रक में रहते तो बुरी तरह घायल हो जाते। उन्होंने तुरंत ही घटना की जानकारी पुलिस को दी है। फिलहाल मौके पर दोनों ट्रक पड़े हुए हैं।

उत्पन्ना एकादशी व्रत अनुष्ठान पूजन समारोह आज

बैतूल। युवा साहू समाज सेवा संगठन जिला बैतूल के तत्वावधान में उत्पन्ना एकादशी व्रत पूजन अनुष्ठान समारोह का आयोजन 26 नवंबर दिन मंगलवार को दोपहर 12 बजे से कोसमी स्थित श्रीमती चंद्रकला साहू के निवास पर आयोजित की जाएगी। संगठन के माध्यम से यह 55वीं एकादशी का आयोजन लगातार किया जाएगा। पंडित नरेंद्र दुबे ने बताया कि श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करने के लिए एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण माना जाता है। श्री हरि विष्णु की पूजा करने से साधक को सभी दुख कष्ट और पापों से छुटकारा मिलता है। पंडित नरेंद्र दुबे ने बताया कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को आरोग्य संतान सुख की प्राप्ति मोक्ष और पापों से मुक्ति मिलती है और प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहती है। संगठन के पदाधिकारी ने सभी से उपस्थित रहने का आग्रह किया है।

बैतूल दहेज प्रकरण में हुआ फैसला

बैतूल। आरक्षी गृह बैतूलबाजार ने आरोपी डॉक्टर योगेश खातरकर एवं उसके परिवार के तीन अन्य सदस्यों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 ए एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध क्रमांक 145/2018 में मामला कायम कर न्यायालय में पेश किया था। आरोप यह था कि यह लोग प्रार्थिया (योगेश की पत्नी) को दहेज में 5 लाख रुपए और कार के लिए शादी के बाद से ही परेशान करने लगे थे। अभियोजन ने आरोप सिद्ध करने के लिए प्रार्थिया उसके अन्य रिश्तेदार सुरजा नागले, पार्वती नागले, दिनेश शेषकर एवं विवेचक सुमन मिश्रा के कथन करवाए थे। प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी बैतूल ने न्यायालय में चले उक्त दांडिक प्रकरण 799/2018 में लगाए आरोपों को सच नहीं माना एवं सभी आरोपियों को पूरी तरह दोषमुक्त कर दिया। आरोपियों की ओर से पैरवी युवा अधिवक्ता सजल गर्ग, राघवेंद्र रघुवंशी एवं सूरतराम धुर्वे ने की।

जनपद स्तर पर होने वाली बैठकों में अनिवार्य रूप से विकासखंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे

सात दिवस के भीतर पूर्ण आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य : कलेक्टर

बैतूल। जनपद स्तर पर आयोजित होने वाली विभिन्न समीक्षा बैठकों में विकासखंड स्तरीय अधिकारी अनिवार्य रुप से उपस्थित रहेंगे। कोई भी अधिकारी अपने प्रतिनिधि को बैठक में नहीं भेज सकेगा। ब्लॉक लेवल अधिकारी बैठक में अनुपस्थित पाए जाने पर संबंधित अधिकारी का वेतन काटने से लेकर विभागीय जांच सहित अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह निर्देश कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित टीएल बैठक में दिए। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने बैठक में विभिन्न विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री अक्षत जैन, एडीएम राजीव नंदन श्रीवास्तव, संयुक्त कलेक्टर मकसूद अहमद सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहें। उन्होंने स्वनिधि भी स्वाभिमान भी भी योजना की निकायवार समीक्षा पर सभी सीएमओ को पीएम स्वनिधि योजना के प्रकरणों को स्वीकृत और वितरित कराने में गति लाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने मैं भी डिजिटल अभियान की समीक्षा कर सभी सीएमओ को निकायवार निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ईकेवाईसी और आधार सीडिंग की कार्यवाही भी पूर्ण करने और स्वामित्व योजना में आरओआर एंट्री से लेकर अंतिम प्रकाशन की कार्यवाही समय पर करने के निर्देश सभी तहसीलदारों को दिए। आयुष्मान योजना की समीक्षा कर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने 7 दिवस के अंदर 70 प्लस आयु के वरिष्ठ नागरिकों और रेगुलर आयुष्मान कार्ड के लक्ष्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम की लीडरशिप लें। अपने क्षेत्र के जनपद सीईओ, सीएमओ, बीएमओ के माध्यम से शेष बचे आयुष्मान कार्ड शीघ्र बनवाएं।

जननी सुरक्षा योजना के भुगतानों का निराकरण कर सीएमएचओ को निर्देशित किया कि जननी सुरक्षा योजना के तहत भुगतान के प्रकरणों का निराकरण कराएं। जन औषधि केंद्र का प्रभावी ढंग से संचालन कराएं। जन औषधि केंद्र पर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता रहे यह सुनिश्चित कराएं। साथ ही सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयुष्मान योजना के तहत पेनल्ड सभी अस्पतालों की सूची चस्पा की जाए। ताकि हितग्राहियों को योजना का लाभ लेने में असुविधा न हो। उन्होंने सिकलसेल एनीमिया के लक्ष्य के विरुद्ध कन्फेट्री कीट उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

मंडियों में सफाई, पेयजल की रहे सुविधा – कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने बैठक मंडी सचिव और समस्त एसडीएम को निर्देशित किया कि मंडियों में व्यवस्थाओं को सुधारे। मंडियों में साफ सफाई, पेयजल आदि मूलभूत व्यवस्थाएं रहें। किसानों को समय पेमेंट मिले। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि मंडियों में वित्तीय धोखाधड़ी पर मंडी सचिव की जिम्मेदारी तय की जाएगी। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने बैठक में सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों की भी विभागवार समीक्षा की और शिकायतों का पूरी गंभीरता से सतत निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीपीग्राम पर दर्ज शिकायतों का भी प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग को केसीसी के प्रकरणों के स्वीकृति और वितरित कराने में गति लाने के निर्देश दिए।

प्रमुख स्थानों पर अलाव जलाने के दिये निर्देश

जिले में बढ़ती ठंड को देखते हुए कलेक्टर ने सभी नगरीय निकायों में प्रमुख स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि कोई भी व्यक्ति बाहर सोता न मिले यह सुनिश्चित करें। रेन बसेरों का अच्छे से संचालन कराएं। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर होमस्टे डेवलप करने के लिए लोगों को प्रेरित करने के निर्देश दिए। कहा कि होम स्टे के लिए अनुदान सहायता के संबंध में भी उन्हें जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि सभी जिला अधिकारी अपने कार्यालय की छत की एरिया जानकारी उपलब्ध कराएं। ताकि रूफ टॉप सोलर पैनल के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जा सकें।

सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित

टीएल बैठक के पश्चात सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सडक़ सुरक्षा से जुड़े पालन प्रतिवेदन और आगामी एजेंडे पर चर्चा की गई। बैठक में बरेठा घाट पर क्षतिग्रस्त सडक़ की यथाशीघ्र मरम्मत कराने के निर्देश एनएचएआई को दिए गए। सभी नगरीय निकायों और जनपदों को निर्देश दिए गए कि मवेशियों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाएं। निराश्रित मवेशियों को गौशालाओं में शिफ्ट किया जाएं। सभी ब्लैक स्पॉट्स और टर्निंग पॉइंट्स पर सुरक्षा के सभी आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए गए। ट्रैक्टर ट्रॉली पर रिफलेक्टर लगाने और हेलमेट अभियान चलाने के भी निर्देश बैठक में दिए गए।

बास्केटबॉल की नेशनल प्रतियोगिता खेलकर आए वंश का सम्मान किया

जिला बास्केटबॉल संघ बैतूल ने ट्रॉफी, ट्रैक सूट के साथ माला पहनाकर किया स्वागत

बैतूल। 68वीं राष्ट्रीय शोलय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेकर बैतूल पहुंचे बास्केटबॉल खिलाड़ी वंश बोरखडे का जिला बास्केट बॉल संघ बैतूल ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बास्केट बॉल संघ बैतूल के सदस्यों सहित कई खेल प्रेमी मौजूद थे। गौरतलब है कि वंश बोरखड़े वरिष्ठ बास्केटबॉल खिलाड़ी संजय बोरखडे के सुपुत्र हैं। उन्होंने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए खेल को अपने जीवन का हिस्सा बनाया और अब मध्यप्रदेश की नेशनल प्रतियोगिता में धमाकेदार प्रदर्शन करके बैतूल लौटे हैं। यह प्रतियोगिता राजनांदगांव (छत्तीगढ़) में आयोजित की गई थी। वंश के सम्मान और स्वागत समारोह के दौरान जिला बास्केटबॉल संघ के संरक्षक राजेंद्र सिंह किलेदार, अध्यक्ष योगी खण्डेलवाल, उपाध्यक्ष बलदेव अरोरा, मुकेश खण्डेलवाल, अजय भार्गव, मनीष वर्मा, सचिव रविन्द्र गोठी, सह सचिव अशोक पंवार, हर्ष खातरकर, कोषाध्यक्ष अभिनित सरसोदे, आदित्य भार्गव, कार्यकारिणी सदस्य संजय बोरखड़े, राजेश वडियालकर, तरूण घोडकी, सारंग झारिया, सुमित भावसार, आदित्य पचौली आदि मौजूद थे।

सागौन के अवैध परिवहन पर की गई सख्त कार्रवाई

आरोपी को 7 दिसंबर तक ज्यूडिशियल रिमांड के आदेश

बैतूल। उत्तर बैतूल (सा.) वन मंडल के परिक्षेत्र बैतूल (सा.) में 18 एवं 19 अक्टूबर 2024 को वन विभाग द्वारा रात्रि गस्ती के दौरान खारी बीट में सागौन की लकड़ी से भरा अशोक लीलैंड मिनी ट्रक जब्त कर वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। इस प्रकरण में 25 नवंबर 2024 को आरोपी रामकुमार मेहरा को मेडिकल परीक्षण उपरांत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां से माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण की विवेचना में आरोपी के द्वारा किए गए अपराध एवं पूर्व में किए गए अपराधों के आधार पर आरोपी को 7 दिसंबर 2024 तक ज्यूडिशियल रिमांड का आदेश दिया गया है। प्रकरण में कार्यवाही प्रचलित है।

उल्लेखनीय है कि अवैध कटाई में संलिप्त वन माफियाओं को पकड़ने की मुहिम के तहत उत्तर बैतूल (सा.) वन मंडल के परिक्षेत्र बैतूल (सा.) में 18 एवं 19 अक्टूबर 2024 को वन विभाग द्वारा रात्रि गस्ती के दौरान खारी बीट में सागौन की लकड़ी से भरा अशोक लीलैंड मिनी ट्रक जप्त कर वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। वाहन की जांच करने पर वाहन में से रामकुमार वल्द पुरुषोत्तम मेहरा के नाम का ड्राइविंग लाइसेंस की छायाप्रति प्राप्त हुई, जिसके आधार पर वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल श्री नवीन गर्ग के निर्देशन में उप वनमंडलाधिकारी बैतूल (सा.) श्रेयस श्रीवास्तव, परिक्षेत्र अधिकारी बैतूल (सा.) श्री के.एस. बघेल द्वारा अलग-अलग दल गठित कर विभिन्न स्थलों पर छापामार कार्यवाही कर आरोपी वाहन चालक सह वाहन मालिक रामकुमार मेहरा साकिन राहुल नगर मंडीदीप जिला रायसेन को गिरफ्तार कर बयान दर्ज किये गये। आरोपी द्वारा अपने इक्यालिया बयान में यह बताया गया कि उसके द्वारा राजू वाडिवा निवासी ग्राम पाठई तहसील शाहपुर के साथ में सागौन वृक्षों की कटाई कर परिवहन किया गया है। इस प्रकरण में वन विभाग की सतत कार्यवाही में पहले ही 27 अक्टूबर 2024 को तीन आरोपियों राजा पिता राजू वाडीवा, शेख अफजल और पाढर के सोनू मुईनुद्दीन की गिरफ्तारी की जा चुकी है।

कैसे आत्मचिंतन के जरिए अपने जीवन में संतुलन और आनंद लायें : राज्य आनंदम संस्था

क्षमता विकास पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों ने सीखे आनंद के गुर

बैतूल। जनपद पंचायत बैतूल के सभागृह में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए एक दिवसीय अल्प विराम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला नोडल अधिकारी सतीश पवार के मार्गदर्शन और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की जिला समन्वयक प्रिया चौधरी की उपस्थिति में हुआ। राज्य आनंद संस्थान भोपाल से मास्टर ट्रेनर प्रदीप महतो, इटारसी से सुमन सिंह, बैतूल से तूलिका पचौरी, दिलीप गीद, जिला संपर्क व्यक्ति महेश गुंजेले, आनंदम सहयोगी आशीष पचौरी, आनंदक आशीष कोकने उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लगभग 70 छात्र-छात्राओं और मेंटर्स ने हिस्सा लिया। लाइफ बैलेंस शीट, रिश्ते, और फ्रीडम ग्लास जैसे विषयों पर संवाद सत्र आयोजित किए गए। मास्टर ट्रेनर ने छात्रों को

अल्पविराम के माध्यम से आत्मचिंतन और अंतरमन से संवाद करने की महत्ता को समझाया। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के मेंटर भूपेंद्र पवार, इंद्रदेव कवडक़र, सुनील पवार और जयश्री देशमुख ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने छात्रों को आत्मविश्लेषण और सकारात्मक सोच के माध्यम से जीवन में आनंद का संचार करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को यह सिखाया गया कि कैसे आत्मचिंतन के जरिए अपने जीवन में संतुलन और आनंद लाया जा सकता है। अल्प विराम का मुख्य संदेश यह था कि खुद को पहचानने और अंतरमन से संवाद करने में ही सच्चा आनंद निहित है। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि इस आयोजन ने उन्हें अपने जीवन को नई दृष्टि से देखने और सकारात्मकता को अपनाने की प्रेरणा दी।

158 बालक, बालिकाओं की 37 लाख से अधिक की राशि स्वीकृत

स्पॉन्सरशिप योजना में 285 बालक-बालिकाओं को 61 लाख से अधिक की राशि स्वीकृत

बैतूल। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत जिले के पात्र हितग्राहियों को राशि स्वीकृत कर उन्हें लाभान्वित किया है। उल्लेखनीय है कि महिला एवं बाल विकास विभाग म.प्र. द्वारा 18 वर्ष की आयु तक के देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के संबंध में समेकित बाल संरक्षण योजना (मिशन वात्सल्य) अंतर्गत मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, स्पांसरशिप योजना, कोविड-19 बाल सेवा योजना एवं पीएम केयर्स योजना बैतूल जिले में संचालित है। उक्त योजनाओं के पात्र हितग्राही बालकों को कलेक्टर श्री सूर्यवंशी द्वारा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के कुल 158 बालक, बालिकाओं को 4 हजार रुपए प्रतिमाह के मान से माह अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 तक की राशि 37 लाख 92 हजार की राशि जारी की है। इसी प्रकार स्पांसरशिप योजना के कुल 285 बालक, बालिकाओं को प्रतिमाह 4 हजार रूपए के मान से माह अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 तक की राशि 61 लाख 20 हजार रुपए तथा पीएम केयर्स योजना में 5 बालक, बालिकाओं को प्रतिमाह 4 हजार के मान से माह अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 तक की राशि 1 लाख 20 हजार रुपए स्वीकृत कर संबंधितों के संरक्षक के साथ संयुक्त बैंक खाते में जमा की गई है।

स्व. विजय कुमार खंडेलवाल बाबूजी की स्मृति में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता 29 दिसंबर को

1.80 लाख रुपये इनाम राशि के साथ दिलबहार चौक पर होगा आयोजन

बैतूल। जिला बॉडीबिल्डिंग संगठन द्वारा स्व.विजय कुमार खंडेलवाल बाबूजी की स्मृति में राज्य स्तरीय बॉडीबिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता 29 दिसंबर रविवार को दिलबहार चौक गंज, बैतूल में संपन्न होगी। प्रतियोगिता में 1.80 लाख रुपये की कुल इनाम राशि निर्धारित की गई है। 25 नवंबर को आयोजित बैठक में बताया गया कि इस प्रतियोगिता में राज्यभर से लगभग 300 खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। खिलाडयिों और निर्णायकों के रहने, खाने और नाश्ते की समुचित व्यवस्था की जिम्मेदारी संगठन के पदाधिकारियों को सौंपी गई है। इस कार्यक्रम में स्टेट बॉडीबिल्डिंग संगठन, उज्जैन से 20 जजों को आमंत्रित किया गया है। उनके ठहरने और अन्य व्यवस्थाओं का

जिम्मा भी समिति के सदस्यों को दिया गया है। इस आयोजन के संबंध में 24 नवंबर को बैतूल जिला बॉडीबिल्डिंग संगठन की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अध्यक्ष रंजीत शिवहरे ने सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की और पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी। बैठक में संगठन के अध्यक्ष रंजीत शिवहरे के साथ-साथ संरक्षक प्रमोद अग्रवाल, अरुण किलेदार, वीरेंद्र अग्निहोत्री और विशाल भद्रे उपस्थित रहे। बैठक में संगठन के उपाध्यक्षों में विवेक मालवीय, बिट्टू बोथरा, धीरज हिरानी, रजनीश जैन, राजू अग्रवाल, मोहन अग्रवाल, राकेश शर्मा और विक्की मिश्रा ने अपनी जिम्मेदारियां लीं। सचिव उमाकांत मालवीय और जितेंद्र मालवीय ने प्रतियोगिता की तैयारियों की रूपरेखा साझा की। कोषाध्यक्ष बाबा अविनाश सोनी ने आयोजन के लिए धनराशि का प्रबंधन सुनिश्चित किया। कार्यकारिणी अध्यक्ष रवि लोट, सदस्य शाहिद अहमद, वतन मिश्रा, विजय भोलू देशमुख, और अन्य सदस्यों ने कार्यक्रम को सफल बनाने की दिशा में अपने योगदान का संकल्प लिया। बैतूल जिला बॉडीबिल्डिंग संगठन ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सहयोग की अपील की है।

एकता और सद्भाव की शपथ के साथ एम्स में फ्लैग डे 2024 मनाया

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के नेतृत्व में एम्स भोपाल ने 25 नवंबर, 2024 को फ्लैग डे मनाया और साम्प्रदायिक सद्भावना सप्ताह के समापन के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 'विविधता में एकता' के संदेश को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय गौरव को मजबूत करना था। कार्यक्रम में प्रो. सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने फ्लैग डे और साम्प्रदायिक सद्भावना के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, फ्लैग डे हमारी साझा पहचान का उत्सव है, जो तिरंगे के माध्यम से सभी भारतीयों को एकजुट करता है। प्रो. सिंह ने एम्स भोपाल को मिनी भारत की तरह बताया क्योंकि यह भारत की सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक विविधता का जीवंत उदाहरण है। इस संस्थान में देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए संकाय सदस्य, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारी मिलकर काम करते हैं, जो 'विविधता में एकता' की भावना को प्रकट करता है। यहां उपचार के लिए आने वाले मरीज भी देश के विभिन्न कोनों से होते हैं, जिससे यह स्थान अलग-अलग सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमियों का संगम बनता है।

इस अवसर पर कई गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जिनका उद्देश्य साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम में कर्मचारियों ने सद्भावना शपथ लिया। कार्यक्रम के दौरान मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर टीम ने 'मेरी पहचान मेरा देश' थीम पर एक नाटक प्रस्तुत किया। इस नाटक ने देशभक्ति और सांस्कृतिक विविधता में एकता की भावना को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया। साथ ही एक हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया गया, जिसमें साम्प्रदायिक सद्भाव और फ्लैग डे के प्रति समर्थन व्यक्त किया गया। इस कार्यक्रम में प्रो. शशांक पुरवार (कार्यवाहक मेडिकल अधीक्षक) के साथ-साथ अन्य फैकल्टी सदस्यों, रेजिडेंट डॉक्टरों और मरीजों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम एम्स भोपाल में आयोजित साम्प्रदायिक सद्भावना सप्ताह की समापन कड़ी थी, जिसने राष्ट्रीय एकीकरण और सद्भावना के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता को दोहराया।

कांग्रेस राज में घट रही थी बेटियों की संख्या, भाजपा राज में बढ़ रही है : श्रीमती माया नारोलिया

महिला अत्याचारों पर सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाना जानती है कांग्रेस

केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं से बेटियां बन रहीं आत्मनिर्भर

भोपाल (नप्र)। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्रीमती माया नारोलिया ने कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुश्री साधना भारती एवं महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती नूरी खान द्वारा पत्रकार-वार्ता में प्रदेश सरकार पर लगाए आरोपों को कांग्रेस की नौटंकी बताते हुए कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता महिला अत्याचारों को लेकर सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाना जानते हैं। ये बेटियों की आबरू और उन पर होने वाले अत्याचारों को भी राजनीति के चश्मे से देखते हैं और ऐसे मामलों में इनका विरोध सिर्फ भाजपा शासित राज्यों तक ही सीमित होता है। राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे सतत प्रयासों ने महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाया है। मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार पहले लाड़ली लक्ष्मी योजना और अब लाड़ली बहना योजना के माध्यम से न केवल बहनों को आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि समाज में सम्मानजनक स्थान प्रदान करने के लिए स्थानीय निकायों में उन्हें 50 प्रतिशत आरक्षण भी दे रही है। देश में पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए प्रावधान किया है। यही नहीं, बल्कि महिला स्वसहायता समूहों को मदद, लखपति दीदी योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना, उज्जवला योजना आदि के माध्यम से महिलाओं के कल्याण के लिए भाजपा की सरकार जमीनी प्रयास कर रही है।

प्रदेश का वातावरण बहनों, बेटियों के लिए अनुकूल- महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्रीमती माया नारोलिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें बहन-बेटियों की सुरक्षा, उनके अधिकार और उनके कल्याण के प्रति कितनी संवदेनशील हैं, इसके लिए भाजपा सरकार को कांग्रेस के किसी नेता से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में आ रहा बड़ा सामाजिक परिवर्तन और बढ़ते लिंगानुपात के आंकड़े ये बताते हैं कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने बेटियों, बहनों की बेहतरी के लिए बहुत काम किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर दिग्विजय सिंह सरकार के समय के लिंगानुपात के आंकड़े और आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार के समय के आंकड़े देख लें, तो उन्हें खुद ही जवाब मिल जाएगा। प्रदेश में प्रति हजार बेटों पर हर साल जन्म लेने वाली बेटियों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि ये बताती है कि प्रदेश का वातावरण बहनों, बेटियों के लिए कितना अनुकूल है।

अन्य राज्यों के मामलों पर क्यों चुप्पी साध लेते हैं कांग्रेसी?

महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्रीमती माया नारोलिया ने कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली कांग्रेस नेत्री प्रियंका वाड्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती या फिर नूरी खान हों इन्हें महिला उत्पीड़न की सिर्फ वो ही घटनाएं दिखाई देती हैं, जो मध्यप्रदेश या भाजपा शासित अन्य राज्यों में घट रही हो। राजस्थान में गहलोत सरकार के समय महिलाओं पर कितने अत्याचार हुए, लेकिन कांग्रेस की इन नेत्रियों को दिखाई नहीं दिए। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर महिला कांग्रेस की किसी नेत्री ने मुंह खोलना भी ठीक नहीं समझा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाने से पहले घड़ियाली आंसू बहाने वाली कांग्रेस की इन नेत्रियों को यह देखना चाहिए कि मध्यप्रदेश ही देश का वो पहला राज्य है, जिसने बेटियों से दुष्कर्म के आरोपियों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की हर घटना में भाजपा की सरकार बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई करती है और महिला उत्पीड़न या अत्याचार के हर मामले में कानून अपना काम करेगा।

एम्स भोपाल में स्किन बैंक की शुरुआत जलन और घावों के उपचार में नई क्रांति

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में एम्स भोपाल में आज स्किन (त्वचा) बैंक का उद्घाटन किया गया। यह विशेष सुविधा मानव त्वचा प्रत्यारोपण (स्किन एलोग्राफ्ट) के संग्रह, प्रसंस्करण, संरक्षण और वितरण के लिए समर्पित है। यह पहल गंभीर रूप से जले हुए घावों और अन्य त्वचा संबंधित चोटों के इलाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर प्रो. सिंह ने कहा, एम्स भोपाल में स्किन बैंक की स्थापना संस्थान और पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जलन और घावों के उपचार में संरक्षित त्वचा की उपलब्धता जीवन बचाने में सहायक होती है।

एम्स भोपाल के बर्न्स और प्लास्टिक सर्जरी विभाग द्वारा संचालित यह स्किन बैंक 24×7 कार्यरत रहेगा। यह सुविधा सुरक्षा और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों का पालन करती है, जिसमें स्टाफ का सतत प्रशिक्षण और नियमित गुणवत्ता नियंत्रण शामिल है। स्किन बैंक चिकित्सा आपात स्थितियों में स्किन एलोग्राफ्ट की बढ़ती मांग को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे ज़रूरतमंद रोगियों को नई ज़िंदगी मिलेगी। इस कार्यक्रम में प्रो. शशांक पुरवार (कार्यवाहक मेडिकल अधीक्षक), बर्न्स और प्लास्टिक सर्जरी के विभागाध्यक्ष प्रो. (डॉ.) मनल मोहम्मद खान, (डॉ.) दीपक कृष्णा, एडिशनल प्रोफेसर बर्न्स एवं प्लास्टिक सर्जरी के साथ-साथ अन्य फैकल्टी सदस्यों और रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी भाग लिया। एम्स भोपाल का यह स्किन बैंक आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से सुसज्जित है, जो त्वचा के दान, उसके प्रसंस्करण और भंडारण को सुनिश्चित करेगा, ताकि मरीजों को समय पर जीवनरक्षक उपचार उपलब्ध कराया जा सके।

एम्स भोपाल के डॉ. बालकृष्णन ने एनएपीटी सम्मेलन 2024 में फार्माकोविजिलेंस में एआई के उपयोग पर प्रस्तुति दी

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में संस्थान ने अकादमिक उत्कृष्टता, नवाचार और साझाकरण की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। इसी कड़ी में, एम्स नागपुर में 21 और 22 नवंबर 2024 को आयोजित नेशनल एसोसिएशन ऑफ फार्माकोलॉजी एंड थैरेप्यूटिक्स (एनएपीटी) के तीसरे वार्षिक सम्मेलन में एम्स भोपाल के फार्माकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष

डॉ. बालाकृष्णन एस ने फार्माकोविजिलेंस में सिग्नल डिटेक्शन के उभरते रुझान पर एक महत्वपूर्ण सत्र प्रस्तुत किया। प्रो. सिंह ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा-फार्माकोविजिलेंस का क्षेत्र मरीजों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिग्नल डिटेक्शन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग क्रांतिकारी कदम है, जो न केवल प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं (एडीआर) की पहचान के समय को कम करेगा, बल्कि समग्र प्रिस्क्राइबिंग प्रथाओं को भी बेहतर बनाएगा।

डॉ. बालाकृष्णन ने सिग्नल डिटेक्शन की नवीनतम विधियों पर चर्चा की, जो प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं (एडीआर) की पहचान में सहायक हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सिग्नल डिटेक्शन प्रक्रिया में एआई के उपयोग से समय में काफी बचत हो सकती है, जिससे त्वरित प्रतिक्रिया और सुरक्षित प्रिस्क्राइबिंग प्रथाओं, रोगियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणाम सुनिश्चित करेंगे।

एम्स भोपाल में माताओं और शिशुओं के लिए 'हैप्पी बेबी ज़ोन' का शुभारंभ

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में एम्स भोपाल में माताओं और शिशुओं की भलाई को ध्यान में रखते हुए, 'हैप्पी बेबी ज़ोन' के तहत तीन विशेष ब्रेस्टफीडिंग काउंटर्स शुरू किए हैं। ये काउंटर्स माताओं को सुरक्षित, आरामदायक और निजी स्थान प्रदान करते हैं, जहां वे अपने बच्चों को स्तनपान करा सकती हैं और डायपर भी बदल सकती हैं। इस अवसर पर प्रो. सिंह ने कहाः 'हैप्पी बेबी ज़ोन' एम्स भोपाल की माताओं और शिशुओं के प्रति समर्पण को दर्शाता है। स्तनपान के लिए सुरक्षित और निजी स्थान प्रदान करना न केवल माताओं के आराम के लिए बल्कि शिशुओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। हमें उम्मीद है कि यह पहल इस क्षेत्र में इसी प्रकार की अन्य पहलों के लिए एक मिसाल बनेगी।

हैप्पी बेबी ज़ोन को माताओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। यह सुविधा न केवल निजता और सुविधा प्रदान करती है, बल्कि बच्चों की देखभाल को आसान और तनाव मुक्त बनाती है। कार्यक्रम के दौरान प्रो. सिंह ने एक मां और उनके बच्चे से बातचीत की और उन्हें हिमालय बेबी केयर द्वारा प्रायोजित उपहार भेंट किया। इस कार्यक्रम में प्रो. शशांक पुरवार (कार्यवाहक मेडिकल अधीक्षक) के साथ-साथ अन्य फैकल्टी सदस्यों, रेजिडेंट डॉक्टरों और मरीजों ने भाग लिया। यह पहल एम्स भोपाल के समग्र दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो चिकित्सा देखभाल के साथ-साथ भावनात्मक और सामाजिक भलाई को भी प्राथमिकता देती है।

प्राचीन तहसील सोहागपुर के ह्रास पर बेबाक

मुफ्तखोरी, घूसखोरी खत्म हो तो भारत बनेगा विश्वगुरू

हीरालाल गोलानी सोहागपुर। समाजसेवी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी रहे बालपुरी गोस्वामी ने वैभवशाली तहसील सोहागपुर को याद करते स्वार्थी नागरिकों पर टिप्पणियां सोशल मीडिया पर की हैं। अपनी बेबाक राय के लिए मशहूर श्री गोस्वामी ने लिखा है कि 'सोते रहो सोये रहो मेरे प्यारे नगरवासियों,हम कहां थे और क्या बचे कभी इस पर भी विचार कर लें। जिले की सबसे बड़ी और वैभवशाली पुरानी तहसील हुआ करती थी सोहागपुर। आज पिपरिया हमारे संलग्न रही जिला बनने जा रही है। जागते हुए वहां निवासियों को कोटि कोटि बधाई। बनखेड़ी तहसील भी बन गई ,और दो..दो गाड़ियों का स्टाप भी हो गया बिना हों हल्ला किये....? पड़ोसी बाबई ग्राम पंचायत नगर पंचायत में बदल गई ,और आज क्षेत्र का सबसे बड़ा औद्योगिक स्थल बन गया है। इस विकास से हमें किसी भी तरह जलन नहीं ।वहां के जागते निस्वार्थी बंधुओं कोटिश बधाई...., में पर प्रश्न यह है कि यह सब सोहागपुर में क्यों नहीं हो सकता था..... कारण स्पष्ट है हम अपने अपने स्वार्थ में लगे रहे , और मोटी चादर ओढ़ सोते रहे और आगे भी सोते रहेंगे....?'

सोता, लुटता, उजड़ता सोहागपुर

जय हो पिपरिया.... जिला पिपरिया।सोहागपुर वासियों धन्यवाद गहरी निद्रा में सोने का मजा ही कुछ और है । धन्यवाद सोहागपुर सुना है पिपरिया 31 दिसम्बर से पूर्व जिला बनने वाला है और शायद राजा भी बजीर की चौखट पर माथा टेकने बाला है... धन्यवाद पिपरिया के ऊर्जा बान वासियों सोता सोहागपुर लुटता सोहागपुर उजड़ता सोहागपुर।

किसानों से माफी मांगते,गौ माता की बात

किसान बंधुओं पर भी सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसान बंधुओं एवं सभी किसान संगठनो से विनम्र निवेदन मेरी हकीकत लेख किसी भाई को थोड़ा सा बुरा लगे तो अपना ही साथी समझ माफ करना । आपने कभी इस पर भी विचार किया है। कि हमको इतनी सारी परेशानी क्यों खड़ी हो रही। कभी डीएपी यूरोप के कभी फसलों के लिए अच्छे दामों के मारे मारे दर दर भटकना पड़ रहा है.... । हमने जब से अपनी पूज्य गौ माता को जो हमारे जीवन का आधार है ।उसे दर दर भटकने को छोड़ा है। घर में हार्वेस्टर, ट्रेक्टर, चार पहिया दो पहिया वाहनों के लिए बड़े बड़े शेड बना लिये हैं ,पर क्या गौ माता के लिए भी बनाया है। यदि वह बिन बोले दर दर भटक रही है । तो फिर आप कैसे खुशी ,सुखी से बैठ सकते हैं यह विचारणीय प्रश्न है?

निजी स्वार्थ, एकाधिकार बना रहे

जो लोग यह कहते है कि सोहागपुर में व्यापार के कोई अवसर नहीं है या तो वे कुछ करना ही नहीं चाहते। या फिर अपने निजी स्वार्थ के चलते यह वातावरण बनाया रखना चाहते ताकि उनका एकाधिकार और बर्चस्व वना रहे। पूर्व में लगभग 1967,1970 में बिना व्यवस्थाओं के चलते गल्ला मंडी चलती थी। यहां व्यापारी जैसे स्वगीर्य छोटेलाल साहू, स्वगीर्य फूलचंद साहू ,श्री डालचंद गुरदयाल फर्म , श्री मांगीलाल कुंजीलाल फर्म जो आज भी हमारे बीच उपस्थित है ।श्री यशवंत जी चौधरी इन सभी व्यापारी बंधुओं के सहयोग काफी अच्छी गल्ला मंडी चली,दोद्दो दाल मीलें चलती थी । वर्तमान में आज भी पोलर का धंधा उससे निर्मित कपड़े पूरे प्रदेश में ही अन्य प्रदेशों में ही नहीं नेपाल आदि में जाते हैं। जिन्हें मैंने स्वयं देखा है जब नेपाल श्री पशुपति नाथ दर्शन के लिए गया था । वहां के दूकानदार से पूछा उसने स्वयं कहा यह भारत में कोई सोहागपुर मंडी का बना हुआ है।मुझे सुनकर आश्चर्य के साथ गर्व भी महसूस हुआ। कि हमारे सोहागपुर की नगरी का बना माल नेपाल में बिक रहा है। हमें गर्व होना चाहिए । सोहागपुर से बनकर लोहा ,पाइप और चादर टीन बनी पेटी बनकर कई क्षेत्रों में एवं मेलों सप्लाई हो रही हैं। सड़ा सा कबाड़ का धंधा फल-फूल रहा है। फिर हम कैसे कह सकते हैं ।कि यहां व्यापार के अवसर नहीं है।सिर्फ और सिर्फ चाहिए ।कुछ करने की इच्छा शक्ति, राजनैतिक एकता और आपसी सहयोग और निजी स्वार्थ का त्याग।...... व्यवसाय बढ़ेगा रोजगार मिलेगा ।जागो सोहागपुर वासियों जागो.....जय सोहागपुर।

बन सकता है भारत विश्वगुरू

अमेरिका का लोहा हर क्षेत्र में दुनिया भर मानता...? पर मैं यह सौ प्रतिशत दावे से कह सकता हूं कि यदि भारत में सिर्फ 'मुफ्त खोरी' 'घूंसखोरी' और 'हरामखोरी' बंद हो जाए तो विश्व का सर्वे सम्पन्न शक्तिशाली देश बन जाएगा भारत ।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल एमएलएनआईटी, प्रयागराज में कुंभ कॉनक्लेव में हुए शामिल

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रयागराज में इंडिया थिंक काउंसिल के तत्वावधान में आयोजित तीन दिवसीय कुंभ कॉनक्लेव के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने उपस्थित बौद्धिक जनों से संवाद करते हुए कुंभ की प्रासंगिकता और इसके महत्व पर विचार साझा किए।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने इस आयोजन को ज्ञान और विचार-विमर्श का एक महत्वपूर्ण मंच बताया, जहां भारत की सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक समरसता पर चर्चा की गई। उन्होंने इस अवसर पर सभी विशिष्ट अतिथियों का अभिवादन करते हुए आयोजकों को उनकी सराहनीय पहल के लिए बधाई दी। कार्यक्रम में केरल के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान, परमार्थ निकेतन आश्रम (ऋषिकेश) के अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी श्री चिदानंद सरस्वती (मुनि जी) और अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे।

हर बूथ भाजपा के साथ हर घर भाजपा का लक्ष्य लेकर कार्य करें कार्यकर्ता: हितानंद

भाजपा कार्यकर्ता सेना की तर्ज पर हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुटे रहते हैं

मैहर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी ने सोमवार को मैहर जिला भाजपा कार्यालय में नवनिर्वाचित बूथ अध्यक्षों और बूथ समिति के सदस्यों का सम्मान करते हुए कहा कि हर बूथ भाजपा के साथ अब हर घर भाजपा का लक्ष्य लेकर कार्यकर्ता कार्य करें। भाजपा कार्यकर्ता सेना की तर्ज पर अपने हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार कार्य में जुटे रहते हैं। बूथ कार्यकर्ता पार्टी की बड़ी ताकत हैं, इसे और मजबूत बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी बूथ अध्यक्षों के सम्मान के लिए निकाली गई रथ यात्रा में शामिल हुए। इससे पहले श्री हितानंद जी ने मैहर शारदा माता मंदिर पहुंचकर मां शारदा का दर्शन व पूजन किया।

भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी ने कहा कि संगठन शक्ति, बूथ समितियों की मजबूती और कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत व परिश्रम से मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक विजय मिली है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बूथ मैनेजमेंट और माइक्रो मैनेजमेंट से ही विजय हासिल हुई है।

हर घर में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होना चाहिए- भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी ने कहा कि आज बूथ अध्यक्षों, बूथ समितियों के सदस्यों का सम्मान कर जो आत्मीय खुशी प्राप्त हुई है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता संगठन के दिशा-निर्देश पर सेना की तर्ज पर कार्य करते हैं। जिस तरीके से सेना देश की रक्षा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिन-रात एक करके कार्य में जुटी रहती है, उसी प्रकार भाजपा कार्यकर्ता भी लक्ष्य प्राप्त करने तक कार्य में जुटे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन पर्व के तहत मध्यप्रदेश सहित देशभर में करोड़ों भारतवासी भाजपा परिवार का हिस्सा बने हैं। संगठन पर्व के तहत पार्टी कार्यकर्ता हर घर भाजपा का लक्ष्य लेकर कार्य करें और अपने-अपने बूथ पर संगठन को और मजबूती प्रदान करें। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि प्रदेश के हर घर में कम से कम भाजपा का एक सदस्य अवश्य होना चाहिए।

सम्मान कर कराया नगर भ्रमण, हुई आतिशबाजी- भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी ने मैहर के जिला कार्यालय में जिले के सभी बूथ अध्यक्षों का सम्मान किया। सम्मान के बाद बूथ अध्यक्षों को वाहन में बैठाकर नगर भ्रमण कराया और आतिशबाजी की गई। नगर भ्रमण यात्रा मैहर जिला भाजपा कार्यालय से अग्रसेन चौक, घंटाघर व नगर बाजार होते हुए घंटाघर पर संपन्न हुई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्री कमलेश सुहाने, विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी, पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसी प्रकार प्रदेश के विभिन्न जिलों में बूथ अध्यक्षों एवं समिति के सदस्यों का सम्मान किया गया।

गीता लीडरशिप कांटेस्ट का आयोजन आज

जिले के 4 छात्रों का होगा चयन, प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपये एवं उज्जैन दर्शन

बैतूल। मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग और इस्कॉन उज्जैन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 10 दिसम्बर 2024 को आयोजित किया जा रहा है। जिला स्तरीय नोडल प्रभारी महेश गुंजेले ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य छात्र-छात्राओं में स्थायी नैतिक मूल्यों का संचार करना, चरित्र निर्माण को प्रेरित करना और आज के युवाओं में व्याप्त विभिन्न व्यसनों के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह मूल्य शिक्षा प्रतियोगिता छात्र-छात्राओं के शैक्षिक पाठ्यक्रम को आवश्यक नैतिक मूल्यों जैसे सत्यनिष्ठा, सहानुभूति,सम्मान और उत्तरदायित्व से समृद्ध बनाने हेतु डिजाइन की गई है और साथ ही उन्हें व्यसनों के हानिकारक प्रभावों के प्रति जागरूक करना है।

पूरे देश से शिरकत करेंगे संविधान विशेषज्ञ, संविधान दिवस आज

बैतूल। भारतीय बौद्ध महासभा, फूले शाहू, आम्बेडकर वरिष्ठ नागरिक जन जागृति समिति के संयुक्त तत्वावधान में कल मंगलवार संविधान दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांसद आलोक शर्मा को जन्मदिन की शुभकामनाएँ, बधाई दी।

सागर जिले में हर खेत पर धारा 144 लागू!

धुआं दिखा तो किसानों को देना होगा 15 हजार तक जुर्माना, जानें मामला

सागर (नप्र)। मप्र के सागर में किसान सकते में हैं! कारण उनके खेतों में भी धारा 144 लागू की गई है। खेत में यदि धुआं उठता नजर आया तो तत्काल खेत मालिक और किसान पर जुर्माना ठोक दिया जाएगा। जुर्माना भी 15 हजार रुपए तक भरना होगा। दरअसल, कलेक्टर सागर ने मानव स्वास्थ्य के मद्देनजर और स्वांस के खतरे के दृष्टिगत आदेश जारी कर दिया है। इस आशय का आदेश सभी प्रशासनिक दफ्तर से लेकर गांव की चौपाल तक चिपकाया जा रहा है।

दरअसल, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में अचानक से बढ़े वायु प्रदूषण और खेतों से उठते धुएं को देखते हुए सागर कलेक्टर सह जिला दंडाधिकारी ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने, सागर जिले की सीमा के अंदर कहीं भी खेत में पराली या नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

सागर में कलेक्टर ने लगाई धारा 144- डीएम के आदेश में स्पष्ट है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत खेत में पराली और नरवाई जलाने वाले किसानों पर जुर्माना लगाया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि धारा 144 के अंतर्गत जन सामान्य, मानव जीवन स्वास्थ्य, स्वांस के खतरे के प्रभाव को दृष्टिगत

रखते हुए सागर जिले के खेत में धान की फसल के अवशेष (पराली) खड़े गेहूं के तलों (नरवाई) एवं फसल अवशेषों में आग लगाए जाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यह भी स्पष्ट किया गया है आग और धुएं से होने से रोकने एवं प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के प्रावधानों का पालन करते हुए नरवाई जलाना तत्समय से तत्काल प्रतिबंधित किया गया है। जो कि वर्तमान में निरंतर प्रतिबंधित रहेगा।

ढाई हजार से 15 हजार तक देना होगा जुर्माना- जिला प्रशासन ने नरवाई और पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माने की राशि का भी प्रावधान किया है। इसमें ढाई हजार से पंद्रह हजार रुपए तक का प्रावधान है। आदेश के अनुसार नरवाई जलाने वाले किसानों में 2 एकड़ तक के किसान पर 2500 रुपए का अर्थदंड प्रति घटना, 2 से 5 एकड़ तक के किसानों को 5000 रुपए का अर्थदंड प्रति घटना तथा 5 एकड़ से बड़े किसानों पर 15,000 रुपए तक का अर्थदंड प्रति घटना के अनुसार वसूला जाएगा।

गांवों में मुनादी के साथ जगह-जगह चिपकाए आदेश- कलेक्टर संदीप जीआर ने कहा कि आदेश की सूचना जन सामान्य को मुनादी द्वारा दी जाए आदेश की प्रतियां कलेक्टर कार्यालय, तहसील कार्यालय, कृषि उपज मंडी, पुलिस थाना, जनपद पंचायत, नगर पालिका, ग्राम पंचायत आदि के सूचना पटल पर चस्पा की जाए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कूनो में गूंजी किलकारियां

मादा चीता निर्वाह ने जन्मे बच्चे

भोपाल (नप्र)। चीता प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क की मादा चीता निरवाह ने अपने शावकों को जन्म दिया है। अधिकारियों का कहना है कि यह डेवलपमेंट चीतों को उनके प्राकृतिक आवास में फिर से लाने के देश के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण माइल स्टोन है। शावकों की सही संख्या अभी तक ज्ञात नहीं है।

चीता प्रोजेक्ट को मिली उम्मीद- 2022 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए चीतों में से एक निरवाह में हाल के हफ्तों में गर्भावस्था के स्पष्ट लक्षण दिखाई दे रहे थे। वन्यजीव अधिकारी उसकी स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहे थे, खासकर जब एक अन्य मादा चीता वीरा को लेकर पहले की उम्मीदें झूठी साबित हुईं। अधिकारियों का कहना है कि निरवाह के शावकों के जन्म से इस परियोजना में नई उम्मीद जगी है।

कूनो में अब 24 चीते- कूनो नेशनल पार्क अब 24 चीतों का घर है, जिसमें पार्क के भीतर पैदा हुए 12 शावक शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस महत्वाकांक्षी पहल की सफलता है, जिसके तहत 1952 में भारत में विलुप्त घोषित की गई प्रजाति को फिर से लाया गया है। इससे पहले वीरा की गर्भावस्था ने शुरू में उत्साह जगाया था, लेकिन आगे की जांच से पुष्टि हुई कि यह एक गलत अलार्म था।

इस झटके के बावजूद, एक अधिकारी ने कहा, निरवाह के सफल प्रसव ने पार्क की फिर से शुरू की गई चीता के प्रजनन स्थल के रूप में क्षमता की पुष्टि की है। कूनो के अधिकारियों ने नवजात शावकों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए अपनी खुशी और प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

जबलपुर में बाघिन के डर से 25 स्कूल बंद, पांच दिन की छुट्टी

घर से बाहर निकलने पर दहशत में लोग

जबलपुर (नप्र)। मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास करंजिया ब्लॉक में एक बाघिन के दिखने से दहशत फैल गई है। इस वजह से 25 स्कूलों में 25 से 29 नवंबर तक छुट्टी घोषित कर दी गई है। बाघिन ने एक मवेशी का शिकार भी किया है। किसान खेतों में जाने से डर रहे हैं। वन विभाग बाघिन पर नज़र रख रहा है और ज़रूरत पड़ने पर उसे दूसरी जगह ले जाने की योजना बना रहा है।

पश्चिमी करंजिया वन परिक्षेत्र के पंडरी पानी गांव और आसपास के इलाकों में पिछले एक हफ्ते से एक बाघिन देखी जा रही है। इससे ग्रामीणों में डर का माहौल है। बाघिन ने दो दिन पहले एक जानवर का शिकार भी कर लिया, जिससे डर और बढ़ गया है। बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने 25 प्राइमरी और मिडिल स्कूल बंद रखने का फैसला किया है।

एक हफ्ते से घूम रही बाघिन- वह पंडरी पानी गांव के जंगल में पिछले एक हफ्ते से बाघिन घूम रही है। रेंजर प्राची मिश्रा ने बताया कि बाघिन ने दक्षिण समनापुर वन परिक्षेत्र के रंजरा गांव में एक मवेशी का शिकार किया था। खेतों में काम करने वाले मजदूर भी डरे हुए हैं। गांव वालों को सतर्क रहने और जंगल में अकेले न जाने की सलाह दी गई है।

लगातार रखी जा रही है नजर- वन विभाग की टीम लगातार बाघिन की निगरानी कर रही है। कैमरों और पेट्रोलिंग टीम के जरिए बाघिन पर नजर रखी जा रही है। शनिवार रात को बाघिन की आखिरी लोकेशन कैमरे में कैद हुई थी। उसके बाद से बाघिन का कोई पता नहीं चला है।

सिंहस्थ 2028 की तैयारियां शुरू

सरकार कराएगी 15,567 करोड़ के विकास कार्य

- मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में 27 मार्च से 27 मई 2028 तक सिंहस्थ महापर्व
- उज्जैन की क्षिप्रा नदी में 9 अप्रैल से 8 मई तक तीन शाही स्नान और सात पर्व स्नान होंगे

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में सिंहस्थ-2028 की तैयारी राज्य सरकार ने शुरू कर दी है। इसके लिए पांच सौ करोड़ रुपये का बजट प्रावधान भी किया गया है। मगर, सिंहस्थ के कार्यों में इससे अधिक व्यय होगा। सिंहस्थ की तैयारियों के तहत 18 विभागों ने 568 कार्यों का प्रस्ताव शासन को सौंपा है।

इन कार्यों में 15,567 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इनमें नदियों पर घाटों का निर्माण, वहां सुरक्षा व्यवस्था, सड़क, पुल निर्माण, सिंहस्थ मेला क्षेत्र का विकास, परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के कार्यों को प्राथमिकता में रखा गया है। वहीं, तीन साल से अधिक अवधि के कार्यों को लेकर भी बजट निर्धारित किया जाएगा।

केंद्र सरकार से मांगा जाएगा बजट- इनमें से अधिकांश कार्यों के लिए केंद्र सरकार से भी बजट मांगा जाएगा। विभागों को केंद्र से सहायता प्राप्त करने के लिए कार्यों का प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल सिंहस्थ 2028 से जुड़ी 19 पहलों के लिए 5,882 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।

इनमें जल संसाधन, नगरीय प्रशासन एवं विकास, ऊर्जा, लोक निर्माण, संस्कृति और पुरातत्व विभागों की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। बताते चलें कि भारत के बारह ज्योतिर्लिंगों में से दो ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में हैं। उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंग और ओंकारेश्वर में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं।

भीड़ संभालने के लिए बनेगी कुशल यातायात प्रणाली- हर 12 वर्ष में पवित्र शहर उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर एक विशेष स्थान रखता है। वहीं, सिंहस्थ में दुनिया भर से लगभग 15 करोड़ आगंतुकों के आने की उम्मीद की जा रही है।

लिहाजा, इतनी बड़ी संख्या में आने वाले भक्तों की भीड़ को संभालने के लिए उज्जैन में एक कुशल यातायात प्रणाली भी बनाई जाएगी। पैदल आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग रास्ता बनाया जाएगा, ताकि वाहनों की वजह से जाम न लगे और लोगों को परेशानी न हो।

प्रारंभिक कार्यों की यह परियोजनाएं स्वीकृत

29.21 किलोमीटर लंबे घाटों का 778.91 करोड़ से निर्माण किया जाएगा और 1,024.95 करोड़ रुपये से कान्ह नदी का 30.15 किलोमीटर का डायवर्जन किया जाएगा।

क्षिप्रा नदी पर सिलारखेड़ी-सेवरखेड़ी बांध के निर्माण से जुड़ी एक सतत जल प्रवाह योजना के लिए 614.53 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

जल विनियमन के लिए क्षिप्रा नदी पर 74.67 करोड़ रुपये से 14 और कान्ह नदी पर 43.51 करोड़ रुपये से 11 प्रस्तावित बैराज बनाए जाएंगे।

198 करोड़ के आवंटन के साथ उज्जैन शहर सीवरेज परियोजना, 250 करोड़ की लागत से अल्ट्रा-हाई-प्रेशर कार्य के लिए एक नया ईएचवी सबस्टेशन, 16.80 करोड़ की लागत से हाई-प्रेशर स्टेशन की क्षमता वृद्धि और 29.83 करोड़ की लागत से 33/11 केवी सबस्टेशन स्थापित किया जाएगा।

4.50 करोड़ 33 केवी लाइन और इंटरकनेक्शन (10 किमी) के निर्माण के लिए अलग रखे गए हैं। 18.36 करोड़ 80 किमी तक फैले समान कार्यों के लिए और 10.08 करोड़ ओंकारेश्वर बजट के तहत भूमिगत केबल कार्य पर व्यय किए जाएंगे।

60 पार नेता नहीं बन पाएंगे भाजपा जिलाध्यक्ष

मंडल अध्यक्ष के लिए 45 से कम उम्र का क्राइटेरिया फिक्स; दिसंबर में होंगे चुनाव

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में बीजेपी बूथ समितियों के चुनाव चल रहे हैं। अगले महीने दिसंबर में मंडल अध्यक्ष और जिलाध्यक्षों के चुनाव होंगे। पहले पखवाड़े में एक से 15 दिसंबर तक मंडल अध्यक्षों के चुनाव होंगे। 16 से 30 दिसंबर तक जिला अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी।

इस बीच दिल्ली में हुई बीजेपी संगठन चुनाव की बैठक में इनके चयन का क्राइटेरिया तय हो गया है। मंडल अध्यक्षों की उम्र 45 साल से कम होगी। वहीं, जिलाध्यक्षों के मामले में भी आयु-सीमा तय की गई है। 60 साल से अधिक उम्र के नेता जिला अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे।

टेक्नीक फ्रेंडली स्ट्रक्चर बनाने की कवायद- बीजेपी ने एमपी के पूरे संगठन को डिजिटलाइज किया है। बूथ समितियों से लेकर मंडल, जिला, संभाग और प्रदेश स्तर तक पूरा सिस्टम डिजिटल है। पार्टी की हर गतिविधि और कार्यक्रम संगठन ऐप के जरिए जनरेट होते हैं। प्रवास से लेकर बैठकों और दौरों की जानकारी भी संगठन ऐप पर ही दर्ज करनी होती है। संगठन में बढ़ते आईटी के उपयोग को देखते हुए बीजेपी अब मंडल और जिलाध्यक्षों के चयन में भी तकनीक फ्रेंडली लीडरशिप को प्रमुखता देगी।

25 दिसंबर तक प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान संभव- बूथ समितियों के चुनाव के बाद मंडल अध्यक्षों का चुनाव 15 दिसंबर तक हो जाएगा। इसके बाद जिला अध्यक्षों के चुनाव होंगे। एमपी में बीजेपी के 60 संगठनात्मक जिले हैं। 50 प्रतिशत जिलों में जिलाध्यक्षों के चुनाव होने के बाद केन्द्रीय नेतृत्व को प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव कराने के लिए सूचना भेजी जाएगी। ऐसे में 25 दिसंबर तक प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो सकती है।

सहमति बनी तो 12 जिलाध्यक्षों को फिर मौका- बीजेपी के प्रदेश में संगठनात्मक रूप से 60 जिले हैं। इनमें से 12 जिले ऐसे हैं जहां जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को एक साल भी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में यदि जिले के नेता और पदाधिकारी सहमत हुए तो इन्हें फिर मौका मिल सकता है। हालांकि जिलाध्यक्ष के रिपीट होने पर भी निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। यानी सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष को रिपीट करने का निर्णय हुआ तो भी निर्विरोध निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और निर्वाचन की तारीख से जिलाध्यक्ष का कार्यकाल गिना जाएगा।

सुपर स्टार राजेश खन्ना को समर्पित खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव

भोपाल गैस त्रासदी पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की होगी स्क्रीनिंग

भोपाल/छतरपुर (नप्र)। दसवां खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 5 दिसंबर से 11 दिसंबर,2024 तक खजुराहो में मनाया जाएगा। अभिनेता एवं आयोजक राजा बुंदेला ने बताया कि यह महोत्सव सुपर स्टार राजेश खन्ना को समर्पित है।

इस फेस्टिवल में अभिनेता अक्षय कुमार, डिंपल कपाड़िया, सुनील शेट्टी, ट्विंकल खन्ना, रघुवीर यादव, अनंत महादेवन, महेश मांजरेकर, अनीश बज्मी, पद्मिनी कोल्हापुरी, मनोज पाहवा एवं सीमा पाहवा, मिर्जापुर फेम फिल्म कलाकार पंकज त्रिपाठी, बोमन ईरानी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी तथा नवीन पांडव एवं सुनील लहरी (रामायण में लक्ष्मण का रोल निभाने वाले कलाकार) सहित

कई विदेशी कलाकार भी इस फिल्म महोत्सव में सम्मिलित होंगे।दसवां खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव सुपर स्टार राजेश खन्ना को समर्पित हैं। वहीं, खजुराहो फिल्म महोत्सव के गवर्निंग काउंसलर के मनमोहन शेट्टी, रजत बेदी, रमेश सिप्पी, प्रकाश झा एवं चंद्रप्रकाश द्विवेदी विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे। अभिनेता सुनील सोन्हिया को फिल्म प्रभारी बनाया है। उन्होंने बताया कि चयनित फिल्मों की स्क्रीनिंग फेस्टिवल में की जाएगी।

सर्व श्रेष्ठ फिल्मों का होगा प्रदर्शन- इस महोत्सव में सर्व श्रेष्ठ फिल्मों का प्रदर्शन पांच टपरा टॉकीज में किया जायेगा। नए कलाकारों के लिए फिल्म एवं रंगमंच, तकनीक कार्य शाला एवं मास्टर क्लास का विशेष आयोजन होगा।

इस कार्यशाला में देश एवं विदेश के प्रतिभागी भाग लेंगे। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली, भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ, मध्यप्रदेश नाट्य विद्यालय, भोपाल के विषय विशेषज्ञ प्रतिभागियों को प्रशिक्षण देंगे।

बीमार मां को देखकर लौट रहे तीन दोस्तों की मौत

जीप ने बाइक को पीछे से टक्कर मारी; इज्तिमा में श्रमदान करने आए थे

भोपाल (नप्र)। भोपाल की नई मंडी के पास स्थित ब्रिज के करीब 80 फीट रोड पर तेज रफ्तार थार जीप ने बाइक सवार तीन दोस्तों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में तीनों की मौत हो गई। मृतकों में एक युवक की मां बीमार हैं। उन्हें देखने के बाद तीनों ऐशबाग के लिए रवाना हुए थे। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। तीनों के शव पीएम के बाद परिजन को सौंप दिए गए हैं।

समीर नजाकत समीर खान अलफैज

छोला मंदिर पुलिस के मुताबिक, अलफैज पुत्र मोहम्मद वसीम (20) निवासी अहमद अली कॉलोनी एशबाग गली नंबर-2, समीर पुत्र हनीफ खान (19) गली नंबर 4 अहमद अली कॉलोनी ऐशबाग और समीर पुत्र नजाकत (18) मूल रूप से लटेरी जिला विदिशा का रहने वाला था। फिलहाल अहमद अली कॉलोनी ऐशबाग में दोस्त के साथ रह रहा था। उसका परिवार करोंद में रहता है। तीनों दोस्त माय किचन नाम की कंपनी में कारपेंटरी का काम करते थे। न्यू मार्केट में उनकी साइट चल रही है। करोंद से समीर पुत्र नजाकत अली को दूर पड़ती थी। पिछले चार महीने से वह दोस्त समीर के घर के करीब किराए से रहने लगा था।

लटेरी में समीर को सुपुर्द खाक किया जाएगा- समीर पुत्र नजाकत अली के शव को परिजन मूल निवास लटेरी लेकर रवाना हुए हैं। उसके शव को असर की नमाज के बाद वहीं सुपुर्द खाक किया जाएगा। जबकि दूसरे समीर खान और अलफैज को भोपाल में ही सुपुर्द खाक किया जाएगा।

रविवार को तीनों दोस्त इटखेड़ी गए थे

इटखेड़ी में होने वाले इज्तिमा में तीनों दोस्त श्रमदान की नीयत से गए थे। यहां से शाम को लौटे तो समीर पुत्र नजाकत अली अपने परिवार से मिलने करोंद चला गया। यहां पिता नहीं थे मां और भाई बहनों से मिलने के बाद वह ऐशबाग के लिए दोस्त समीर और अलफैज के साथ एक ही बाइक पर सवार होकर रवाना हुआ। दरअसल समीर नजाकत की मां इन दिनों बीमार चल रही हैं। नई मंडी के पास स्थित ब्रिज के करीब 80 फीट रोड पर ओवरटेक करते समय एक जीप ने उनके वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में अलफैज की मौके पर मौत हो गई। घटना रविवार रात करीब 11:30 बजे की है। दोनों समीर को हमीदिया अस्पताल पहुंचाया गया था। जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने चंद मिनटों के भीतर ही दोनों को एक-एक कर मृत घोषित कर दिया।

टपकती छत-आग के बाद अब वंदे भारत की स्प्रिंग टूटी

भोपाल (नप्र)। रानी कमलापति-ह. निजामुद्दीन वंदे भारत ट्रेन की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। यात्रियों को होने वाली असुविधा को लेकर इस ट्रेन में नए-नए मामले सामने आ रहे हैं।

ताजा मामला कोच की स्प्रिंग टूटने के कारण ट्रेन के पिछले 10 घंटे से रानी कमलापति स्टेशन पर ही खड़े होना का है। रविवार को जब ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से रात 10.16 बजे वापस लौटी तो कोच नंबर सी-11 की स्प्रिंग टूटी होने की जानकारी मिली थी। जिसके बाद से पिछले 17 घंटे से रानी कमलापति स्थित यार्ड में इसका मेंटेनेंस किया जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन के 10 घंटे लेट होने के बाद नाराज रेल यात्री जहां एक तरफ लगातार रेलवे अधिकारियों के साथ गहमा गहमी करते नजर आ रहे हैं तो कुछ यात्री अब रानी कमलापति स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की पटरियों पर जाकर बैठ गए हैं। नाराज यात्रियों का कहना है कि रेलवे द्वारा कुछ भी हमें नहीं बताया जा रहा है कि ट्रेन आएगी भी या नहीं। लगातार इनको आरपीएफ उठाने का प्रयास कर रही है।

दूसरी तरफ कुछ यात्रियों ने शताब्दी एक्सप्रेस में चढ़ने का प्रयास किया, जिसको लेकर आरपीएफ के जवानों द्वारा यात्रियों को बलपूर्वक उतार दिया गया। दूसरी तरफ मंडल रेल प्रबंधक देवाशीष त्रिपाठी ने बताया की ट्रेन की तकनीकी दिक्कत को दूर कर लिया गया है। ट्रेन भोपाल से शताब्दी के बाद रवाना की जाएगी। यह ट्रेन जल्द रवाना हो सकती है। इसके लिए हम स्टेशन पर अनाउंसमेंट भी करवा रहे हैं।

सूचना नहीं देने पर यात्री हुए नाराज- यात्रियों के अनुसार रेलवे द्वारा उन्हें किसी प्रकार की सूचना नहीं दी जा रही है कि ट्रेन कितने बजे चलेगी। चलेगी भी या नहीं? जिसको लेकर नाराज यात्रियों ने रानी कमलापति स्टेशन पर सुबह करीब 11 बजे अधिकारियों के रूम में हंगामा भी किया।

बार बार री-शेड्यूल से यात्री रहे परेशान, कइयों की छूटी ट्रेन

वंदे भारत में सफर करने वाले यात्रियों ने बताया कि रात करीब 3 बजे उनको रेलवे द्वारा मैसेज किया गया। जिसमें बताया गया की ट्रेन करीब 5 घंटे लेट यानी 10 बजे सुबह चलेगी। जब यात्री 9.45 बजे स्टेशन पहुंचे तो 9.52 पर उन्हें एक और मैसेज दिया गया की ट्रेन अभी आगे भी लेट हो सकती है। इसके बाद यात्रियों ने स्टेशन पर मौजूद अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी और कई यात्रियों ने हंगामा भी किया।

यात्रियों ने कहा- प्रीमियम ट्रेन समझ टिकट लिया लेकिन कोई सुन तक नहीं रहा- इस दौरान यात्रियों ने स्टेशन पर मौजूद अधिकारियों के कमरों में हंगामा किया। एक यात्री गणेश चंद मजूमदार ने कहा कि मैं कोलकाता से आया हूं। मैंने इस ट्रेन में इसलिए टिकट करवाया है कि यह प्रीमियम ट्रेन है।